04 - राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने जासूस यूट्यूबर की चुनौती

05 - समग्र पर्यटन का केंद्र है मध्यप्रदेश

A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 24 मई, 2025

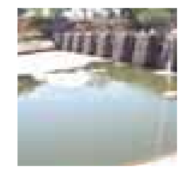
06 - माचना डैम और ताप्ती बैराज के पानी को मिलाकर...

07 - सप्रे संग्रहालय की डिजिटाइजेशन परियोजना से...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 224, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

प्रसंगवश

क्या राष्ट्रपति के सवालों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर पड़ेगा?

बीबीसी ब्यूरो

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट को एक 'प्रेसीडेंशियल रेफ़रेंस' भेजा है। इसमें यह राय मांगी गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गए राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकता है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए इस ज्ञापन में, राष्ट्रपति ने कुछ सवाल पूछे हैं। इन नोट में यह सवाल भी शामिल है कि 'क्या राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू किया जा सकता है?'

इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, यह संघीय ढांचे पर ख़तरनाक प्रहार है और इसका विरोध ज़रूर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोट भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधानमंडल में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव है?

राष्ट्रपति का नोट संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भेजा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत, 'यदि किसी कानून के संबंध में कभी कोई सवाल पैदा हुआ हो या इसकी संभावना हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय ज़रूरी है तो राष्ट्रपति इन सवालों को कोर्ट के पास उसका विचार जानने के लिए भेज सकते हैं।' 'और सुप्रीम कोर्ट, उचित जांच के बाद, राष्ट्रपति को इस पर अपनी राय दे सकता है। आठ अप्रैल को तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार के विधेयकों को अपनी स्वीकृति दी थी, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल का तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों को अपनी स्वीकृति न देना 'अवैध' है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति तथा विधेयकों पर फ़ैसला लेने के लिए समय-सीमा राष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित की थी। तमिलनाडु विधानसभा ने साल 2020 और 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए। ये राज्यपाल आरएन रवि को भेजे गए। राज्यपाल ने इन विधेयकों को लंबित रखा। उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार ने इसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद, राज्यपाल ने 10 विधेयकों को बिना किसी सुझाव के वापस कर दिया। राज्य सरकार ने इन 10 विधेयकों को फिर से पारित किया और उन्हें राज्यपाल के पास दोबारा भेजा। उन्होंने इस बार इन सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय जानने के लिए जो नोट भेजे हैं, उसमें ये 14 सवाल किए गए हैं..

1. जब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के लिए कोई विधेयक भेजा जाता है, तो उनके सामने क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?

2. जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है, तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है?

3. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को संविधान से मिली विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित है?

4. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के काम की न्यायिक समीक्षा पर संविधान का अनुच्छेद 361 पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है?

5. क्या अदालतें राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती हैं? भले ही इसके लिए संविधान ने कोई समय सीमा तय नहीं की हो?

6. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल कोर्ट की समीक्षा के अधीन है?

7. क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के इस्तेमाल के लिए कोर्ट कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है?

8. जब राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्य वजहों से किसी विधेयक को अलग करता है, तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह और राय लेने के लिए बाध्य है?

9. क्या विचाराधीन विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो फ़ैसले लेते हैं, वो उचित हैं? क्या अदालतों को कानून बनने से पहले किसी भी तरह से विधेयक की विषय-वस्तु पर फ़ैसला लेने की अनुमति है?

10. क्या अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कोर्ट के आदेश से राष्ट्रपति/राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों को बदला जा सकता है?

11. क्या राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बिना कानून के रूप में लागू किया जा सकता है?

12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधानों के अधीन, क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पीठ के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके सामने संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दे हैं या नहीं, और उसे कम से कम पांच जजों की पीठ को भेजे?

13. क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों और आदेशों को किसी भी तरह से बदला जा सकता है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत कोई विपरीत आदेश या प्रावधान जारी किया जा सकता है?

14. क्या अनुच्छेद 131 के तहत मिले अधिकारों के अलावा, संविधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर पाबंदी लगाता है?

राष्ट्रपति के रेफरेंस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की बेंच करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से दिए गए गवर्नर के फ़ैसले को पलट सकता है, जिसे 2-जजों की बेंच ने दिया था। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक़, यह रेफ़रेंस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को प्रभावित नहीं करेगा। वो कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 136 और 142 के तहत फ़ैसला दिया है। राष्ट्रपति की तरफ़ से भेजा गया रेफ़रेंस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में अपील या समीक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता। राष्ट्रपति ने केवल एक राय मांगी है। भले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करे, वह केवल एक राय होगी और यह कोई बाध्यकारी उदाहरण या नया निर्णय नहीं होगा। इसलिए, यह पहले से दिया गया फ़ैसला किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

देवी अहिल्याबाई के नाम पर होगा आलमपुर का सरकारी महाविद्यालय

भिंड में सीएम ने की घोषणा

लहार में लगेंगे उद्योग

भिंड (नप्र)। भिंड के लहार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। शुक्रवार को यहां उन्होंने आलमपुर का सरकारी महाविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम पर करने की घोषणा की।

लहार में 100 बीघा जमीन पर पर उद्योग लगाने का ऐलान किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आतंकियों को घर में घुसकर मारने की बात कही। मुख्यमंत्री यहां 117 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इन विकास कार्यों में सड़क, बिजली, जलप्रदाय, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। लहार पहुंचने पर मुख्यमंत्री का हेलीपेड पर स्वागत किया गया। मंच से लेकर 2 किलोमीटर दूर तक रेड कार्पेट बिछाया गया। मंच पर पहुंचते ही सीएम ने हाथ हिलाया, सिर झुकाकर जनता का अभिवादन किया। सीएम की सभा स्थल पर पंडाल में ठंडक बनाए रखने के लिए वाटर स्प्रे लगाए गए हैं, ताकि लोगों को गर्मी न लगे।

2 किमी लंबा रेड कारपेट बिछाया, जेसीबी से फूलों की बारिश - सीएम के स्वागत के लिए पूरे इलाके को सजाया गया था। नई गल्ला मंडी मैदान से लेकर मां मंगला देवी मैदान तक करीब 2 किलोमीटर लंबा लाल कारपेट बिछाया गया था।

मुख्यमंत्री के काफिले पर फूलों की बारिश के लिए 20 से अधिक जेसीबी मशीनें तैनात की गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए अलग-अलग स्थानों पर मंच और स्वागत द्वार सजकर तैयार थे।

शुजालपुर में बस ने बाइक को रौंदा, तीन की मौत

शादी में खाना परोसने जा रहे थे बचपन के दोस्त, बस भोपाल आ रही थी, चालक फरार

शुजालपुर (नप्र)। शाजापुर जिले के शुजालपुर में यात्री बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बस चालक फरार हो गया। हादसा शुजालपुर-आष्टा मार्ग पर शुक्रवार सुबह 8.45 बजे हुआ। बालाजी ट्रेवल्स की बस सारंगपुर से भोपाल की ओर

जा रही थी। जेठड़ा जोड़ के आगे सामने से आ रही बाइक को रौंद दिया। हादसे में आयुष मालवीय (17 साल), रवि मालवीय (19 साल) की मौके पर ही मौत हो गई। राज मालवीय को गंभीर हालत में डायल 100 की टीम ने शुजालपुर मंडी के सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर सिविल अस्पताल से रवाना हो गए हैं। तीनों दोस्तों का अंतिम संस्कार एक साथ होगा। तीनों युवक लसुड़िया घाघ के रहने वाले थे।

- **बिना हेलमेट चला रहे थे बाइक-** मंडी थाना प्रभारी शिवकुमार यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था और सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे मौत हुई। शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। फरार चालक की तलाश जारी है।
- **खराब हाईवे के कारण हुआ हादसा-** स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे का एक कारण स्टेट हाईवे की खराब स्थिति है। सड़क कई जगह से टूटी हुई है, इसमें 6 से 8 इंच तक के गैप हैं। इन दरारों की वजह से वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है। लोगों की शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

चरण छूने योग्य हैं वो पुरुष
जिन्होंने रिश्ता टूट जाने के बाद भी
उस औरत की गरिमा को कभी टूटने
नहीं दिया।
जिनके पास बहुत कुछ था कहने को,
बहुत कुछ था जताने को —
पर उन्होंने चुप रहना चुना,
क्योंकि प्रेम में बदला नहीं,
बस भला चाहना आता था।
वो जान गए थे कि हर सच बोल देना
ज़रूरी नहीं होता,
और हर दर्द बाँट देना इंसाफ़ नहीं होता।
उन्होंने अपने टूटे हुए हिस्सों को
एक रोज़नामचा नहीं बनाया,
क्योंकि जिसे कभी इज्ज़त से चाहा हो,
उसे रुसवा कैसे किया जा सकता है?
ऐसे पुरुष सिर्फ पुरुष नहीं होते,
वो प्रेम की परिभाषा बन जाते हैं —
निस्वार्थ, मौन, और सम्मान से भरे हुए

- निशा शेखावत

बांके बिहारी कॉरिडोर केस फिर से सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

मथुरा (एजेंसी)। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर मंदिर के पुजारी देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने रिव्यू पिटिशन दाखिल की है। जज अब पिटिशन को सुनने पर सहमत हो गई है। उनके वकील सीनियर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह के सामने कहा- मंदिर के फंड को उपयोग करके 5 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने के फैसले में हमारा पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए यह निर्णय एकपक्षीय है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को यूपी सरकार को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के फंड का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए करने की अनुमति दी थी। इस फंड से मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जानी है। शर्त यह रखी गई कि अधिगृहीत भूमि देवता के नाम पर रजिस्टर होगी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने वाले आवेदक देवेंद्र नाथ गोस्वामी मंदिर के पुजारी हैं। सेवायत की राजभोग सेवा से हैं। देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा है- मैं मूल संस्थापक स्वामी श्री हरि दास जी गोस्वामी के वंशज हूं और हमारा परिवार सदियों पुरानी रीति-रिवाजों के अनुसार 500 से ज्यादा वर्षों से मंदिर से जुड़ा है। देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने अर्जी में कहा है- मंदिर के मामलों और धन के और प्रबंधन का मुद्दा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मंदिर के कोष के उपयोग की अनुमति देते समय हमें पक्षकार नहीं बनाया गया। बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए प्रदेश सरकार मंदिर के खजाने की राशि से कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदना चाहती थी। लेकिन, इसका मंदिर के गोस्वामियों ने विरोध किया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाइकोर्ट ने मंदिर के खजाने की राशि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

अयोध्या के 22 साल के लेफ्टिनेंट सिक्किम में शहीद

- हार्टपेशेंट मां को खबर नहीं दी, पिता अमेरिका से रवाना; साथी को बचाने में गई जान

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या के रहने वाले लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी सिक्किम में शहीद हो गए। ऑपरेशनल गश्त के दौरान उनका एक साथी जवान नदी में गिर गया। तेज बहाव में जवान बहने लगा। यह देखकर शशांक नदी में कूद गए। साथी को तो मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लाए, लेकिन खुद जान गंवा बैठे। 22 साल के शशांक का पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंच गया है। कल यानी शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ जमथरा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। शशांक घर के इकलौते बेटे थे। 2019 में उनका सिलेक्शन एनडीए में हुआ था। पिछले साल उन्हें कमीशन मिला और पहली पोस्टिंग सिक्किम में हुई। शशांक की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र के मझवां गद्दोपुर के रहने वाले थे। शशांक के पिता जंग बहादुर तिवारी मर्चेंट नेवी में हैं और वर्तमान में अमेरिका में तैनात हैं। बेटे की मौत का पता चलते ही वह इंडिया के लिए रवाना हो गए। आज शाम या कल सुबह तक उनके अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा सीधे अयोध्या लाया जाएगा। वहां से सेना के अधिकारी पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान तक ले जाएगी।

कोटा में छात्रों की 'आत्महत्या' पर नजर आई 'सुप्रीम' चिंता

- राजस्थान सरकार से पूछा-स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों दे रहे जान
- कहा-इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया है

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्टूडेंट्स सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट्स सुसाइड के मामलों को भी गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं।

आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। 4 मई को एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था। 4 मई को ही,खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था। खड़गपुर सुसाइड को लेकर कोर्ट ने 14 मई को कहा था वो सिर्फ यह पता लगाने के लिए संज्ञान ले रहे हैं कि प्रशासन ने अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में जारी कोर्ट के निर्देशों का पालन कर एफआईआर दर्ज कराई है या नहीं। कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा था।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 38 °c न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 24 मई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

भोपाल में पेड़ से टकराई कार, 3 की मौत

गाड़ी के परखच्चे उड़े, एयरबैग फटे; चेसिस टूटने से दो हिस्सों में बंट गई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल है। मृतकों की पहचान प्रीत आहूजा, विशाल डाबी और पंकज सिसोदिया के रूप में हुई है। प्रीत कपड़े की दुकान चलाता था। विशाल उसी की दुकान में काम करता था। हादसे में घायल राहुल कंडारे को चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट चिरायु अस्पताल के पास गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि पुलिस और एम्बुलेंस सूचना

देने के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची। पोलर व्हाइट कलर की हुन्डई वेन्यू कार प्रीत आहूजा के भाई कमलेश आहूजा के नाम पर रजिस्टर्ड है।

120 किमी/घंटा से ज्यादा थी स्पीड- पुलिस का अनुमान है कि हादसे के समय कार की स्पीड 120 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रही होगी। आम तौर पर स्पीड 100 से 120 किमी प्रति घंटे पर होती है तो हादसे के वक्त एयरबैग फटते नहीं है। इस हादसे में कार के एयरबैग तक फट गए हैं।

पेड़ से टकराने से पहले कार ने सड़क किनारे गुमटी को भी टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद कार दो टुकड़ों में बंट गई। चेसिस भी टूट गया। डैशबोर्ड के नीचे विशाल और प्रीत फंस गए थे। गेट और डैशबोर्ड को काटने के बाद उनकी बॉडी निकाली जा सकी। इस पूरी कवायद में एक घंटे से ज्यादा का समय लगा।

होटल में खाना खाने सीहोर गए थे- परिजन ने बताया- चारों युवक सीहोर के दरबार होटल में खाना खाने गए थे। लौटते समय इंदौर-भोपाल हाईवे पर कार पेड़ से टकरा गई। गाड़ी प्रीत चला रहा था। विशाल उसके बगल वाली जबकि राहुल और कमलेश पीछे की सीट पर बैठे थे।

पंजाब में भ्रष्टाचार केस में एएपी विधायक गिरफ्तार

- घर पर सुबह से विजिलेंस रेड जारी, नोटिस भिजवा सेटिंग कर वसूली के आरोप में एफआईआर

जालंधर (एजेंसी)। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम ने सुबह 8.45 बजे अरोड़ा के अशोक नगर स्थित घर पर रेड की। जिस वक्त विजिलेंस टीम पहुंची, विधायक अरोड़ा कहीं जा रहे थे। विजिलेंस ने घर के नजदीक मंदिर के मोड़ से उन्हें हिरासत में लिया था। इसके बाद टीम उन्हें

घर में ले गई। जिसके बाद अंदर छानबीन की गई। पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस की रेड अभी जारी है। जानकारी के अनुसार विधायक के समधी राजू मदान के घर भी विजिलेंस की एक टीम पहुंची थी, हालांकि टीम को वहां से कुछ नहीं मिला। विधायक का केस कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए एएपी से जुड़ा हुआ है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक विधायक पर आरोप है कि जालंधर नगर निगम के जरिए उन्होंने लोगों को नोटिस भिजवाए। फिर रुपए लेकर नोटिसों को रफा-दफा करा दिया। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अरोड़ा पर ऐक्शन की तैयारी पहले से थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव देवी अहिल्याबाई होलकर महानाट्य मंचन में हुए शामिल

देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती वर्ष में आयोजित किये जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह हम सब का सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश की ऐसी महान शासिका देवी अहिल्याबाई के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को नाट्य मंचन के माध्यम से परिचित होने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कालिदास संस्कृत अकादमी के पण्डित सुर्यनारायण व्यास संकुल सभा गृह में देवी अहिल्या बाई की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर अहिल्या बाई होलकर महानाटय - जीवन, अवदान और वैभव का गान के मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. साधना बलवटे की लिखी पुस्तक ''अहिल्या रूपेण संस्थिता'' का विमोचन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, श्री संजय अग्रवाल, संस्कार भारती के सह कोषाअध्यक्ष श्री श्रीपाद जोशी, श्री विशाल राजोरिया, श्री जगदीश अग्रवाल, देवी अहिल्या बाई जयंती समारोह के जिला

संयोजक श्री उमेश सेंगर, श्री जगदीश पांचाल एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

अतिथियों द्वारा मां सरस्वती और देवी अहिल्या बाई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्कृति संचलनालय के संचालक श्री एन.पी. नामदेव और कालिदास संस्कृत अकादमी के निदेशक ड़ॉ. गोविंद गंधे ने अतिथियों का स्वागत किया।

केन्द्र और राज्य सरकार देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करा रही हैं। देवी अहिल्याबाई ऐसी बेटी थीं, जो विवाह के बाद सास-ससुर की भी बेटी ही बन कर रहीं। बचपन में देवी अहिल्याबाई ने बाजीराव जी की सवारी निकलने पर अपने स्थान से हटने से मना कर दिया था, क्योंकि वे उस समय भगवान शिव की पूजा कर रही थीं, यह प्रसंग उनके साहस को दर्शाता है। देवी अहिल्या बाई सद्गुणों की खान थीं। उन्हें शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी शिक्षा प्रदान की गई थी।

जल गंगा संवर्धन अभियान-2025

गांवों में बनाए जा रहे खेत-तालाब, अमृत सरोवर

'खेत-तालाब' से खेतों तक पानी, किसान लिखेंगे 'समृद्धि' की नई कहानी

भोपाल(नप्र)। किसानों को फसलों की सिंचाई व पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना से विदिशा जिले में खेत-तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। खेत-तालाब व अमृत सरोवर बनने से खेतों को फसलों की आवश्यकता के समय पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। इससे किसान आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिखे सकेंगे। कुओं को रिचार्ज करने के लिए कूप रिचार्ज पिट कुओं का जल स्तर बना कर रखेंगे। परिणाम स्वरूप गर्मियों में भी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा।

विदिशा जिले में 1,819 खेत-तालाब, 21 अमृत सरोवर और 1,709 रिचार्ज पिट्स का निर्माण- जल गंगा संवर्धन अभियान में विदिशा जिले की सभी 7 जनपद (बसौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज और विदिशा) में 21 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 14 अमृत सरोवरों का काम पूर्ण होने को है, शेष 7 पर काम प्रगतिरत है। सभी 7 जनपदों में 1 हजार 731 खेत-तालाब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में लक्ष्य से अधिक 1 हजार 819 खेत-तालाबों का निर्माण हो रहा है। जिले में 1 हजार 400 कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य से अधिक 1 हजार 709 कुओं के रिचार्ज पिट बनाए जाने का काम चल रहा है।

बेहतर जिंदगी का लालच देकर म्यांमार की लड़कियों की हो रही तस्करी

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर अब सिर्फ सुरम्य वादियों और सीमावर्ती सुरक्षा मुद्दों के लिए ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक सामाजिक अपराध के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। म्यांमार से लाई जा रही रोहिंग्या लड़कियों की तस्करी और जबरन शादियों का जाल यहां तेजी से फैलता जा रहा है। म्यांमार की रोहिंग्या बस्तियों में गरीबी और असुरक्षा के माहौल में जी रहीं लड़कियों को भारत में अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर लाया जाता है। लेकिन ये सपना जल्द ही एक डरावनी हकीकत में बदल जाता है। भारत पहुंचते ही इन लड़कियों को उम्र में दो गुने या मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम पुरुषों से जबरन शादी करने को मजबूर किया जाता है। खबर के मुताबिक जम्मू के बठिंडी, सुंजवां, त्रिकुटा नगर और नरवाल जैसे इलाके अब रोहिंग्या बस्तियों से भर चुके हैं। यहीं लड़कियों को कुछ दिन छिपाकर रखा जाता है और फिर सौदा पक्का होते ही उन्हें आगे कश्मीर या अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक, जम्मू और श्रीनगर में अब तक 140 से अधिक लड़कियों की जबरन शादी कराई जा चुकी है। इन लड़कियों की कीमत एक लाख तक तय की जाती है।

75 वर्ष तक बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है: योगी

- बोले मुख्यमंत्री योगी, अयोध्या में चांदी का मुकुट पहनकर लहराई गदा
- कहा-नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, कोई छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं है

अयोध्या (एजेंसी)। सीएम योगी ने कहा-हमें समय रहते मित्र और शत्रु को पहचानना होगा। जिस तरह चतुराई और विवेक से हनुमान जी ने कालनेमि को पहचान लिया था। पाकिस्तान ने 75 वर्ष तक बहुत जी लिया। अब उसका समय आ गया है। वह अपने कर्मों से समाप्त हो जाएगा। 2017 से पहले संत देश में यात्रा पर जाते थे, तो लोग सम्मान का भाव नहीं रखते थे। आज कही भी अयोध्या का नाम लेंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। अयोध्या का नाम सुनते ही लोगों में सम्मान आ जाता है। अयोध्या गुमनाम अस्तित्व को ढूंढ रही थी। हम लोगों ने कसम खाई थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में कही। सीएम ने हनुमानगढ़ी में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेम दास महाराज ने सीएम योगी को चांदी का मुकुट पहनाया और गदा देकर स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की है। योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह नया भारत है, यह किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है।

फ्लाइट के टेक ऑफ-लैंडिंग के वक्त बंद रहेंगी खिड़कियां

- फोटोग्राफी और वीडियो बनाना बैन, देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर नियम लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। डिफेंस एरिया की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने फ्लाइट के टेक ऑफ-लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक पैसेंजर्स के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। यह नियम देश के उन 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर लागू होगा, जिनका इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट के लिए होता है। इसमें अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट शामिल है। 10,000 फीट ऊंचाई तक बंद रखनी होगी फ्लाइट की विंडो

डीजीसीए ने एयरलाइंस, हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन ऑपरेटरों को निर्देश जारी किया है कि डिफेंस एयरफील्ड में आने और जाने वाली उड़ानों में पैसेंजर्स के बगल वाली सीटों की खिड़कियां तब तक बंद रहेंगी जब तक कि विमान टेकऑफ के दौरान 10,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता या लैंडिंग के दौरान नीचे नहीं उतर जाता।

शाह ने बीएसएफ की भूमिका की बांग्लादेश को दिलाई याद

- गृहमंत्री बोले-तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है, यह बिलकुल मत भूलो

बल के 22वें अलंकरण समारोह के अवसर पर की जमकर तारीफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के रोज-रोज के नए पैंतरों पर स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म कैसे हुआ है और उसके निर्माण में भारत के सीमा सुरक्षा बल की क्या भूमिका थी। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि पड़ोसी देश 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उसके निर्माण में बीएसएफ की बड़ी भूमिका को नजरअंदाज न करे। बांग्लादेश के निर्माण में भारत के ऐतिहासिक सहयोग की याद दिलाते हुए शाह ने बीएसएफ की महत्वपूर्ण भागीदारी पर भी जोर दिया। शाह ने ये बातें 22वें सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश को अपने निर्माण में बीएसएफ द्वारा निभाई गई बड़ी भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही शाह ने कहा कि ऑपरेशन

सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर भारत की सैन्य कार्रवाई के विरोध में और आतंकवादियों के समर्थन में भारत पर जवाबी कार्रवाई करने से दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान आंतकवाद का समर्थन करने वाले देश की बन गयी है और वह पूरी तरह बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार-बार दावा करता रहा है कि वह आतंकवाद को समर्थन नहीं देता है लेकिन ऑपरेशन सिन्दूर के बाद के दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है।

भारत के अगले 'ऑपरेशन' को फेल करने में जुटा चीन

बीजिंग (एजेंसी)। चीन क्या पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए चीन ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट की पहुंच का विस्तार पाकिस्तान तक करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 16 मई को एक बैठक की गई है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान की सेना के लिए अपने बेइदो सैटेलाइट सिस्टम की पहुंच का विस्तार करने की बात कही है।

विमान में चीख-पुकार, फिर भी पाक ने नहीं दी परमीशन

टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग, 224 पैसेंजर थे सवार

नई दिल्ली/मुंबई (एजेंसी)। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस (हवा में झटकों) की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयरस्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, पाकिस्तान ने मना कर दिया। न्यूज एजेंसी ने 22 मई को सूत्रों के हवाले से बताया कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर एलएटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने-डुलने लगी। फ्लाइट

में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने-चिल्लाने लगे थे। पायलट ने श्रीनगर एलएटीसी को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा (नोज कोन) टूट गया था। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के भीतर के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। एलएटीसी ने बताया, आखिर हवा में क्या हुआ था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि, 21 मई को इंडियो की आई 321 फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। पंजाब के पठानकोट के पास अचानक मौसम बिगड़ गया। ओले गिरने लगे। पायलट के मुताबिक, उसने इंडियन एयर फोर्स से बाईं तरफ यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ मुड़ने की परमीशन मांगी। जिसे मना कर दिया गया। इसके बाद पायलट ने लाहौर एटीसी से संपर्क कर उनके हवाई क्षेत्र में इंट्री करने की परमीशन मांगी लेकिन लाहौर एटीसी ने

इजाजत नहीं दी। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस ले जाने का प्रयास किया लेकिन तब तक विमान तेज आंधी-बारिश में पहुंच गया। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को मौसम के बीच ले जाने का फैसला लिया। इस दौरान फ्लाइट की स्पीड तेज कर दी। आखिर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की। हालांकि इससे विमान के नोज को नुकसान पहुंचा है। पूरे मामले की जांच डीजीसीए की तरफ से की जा रही है।

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाक ने एयरस्पेस बंद किया बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत, कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयरस्पेस एक महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयरस्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है।

इंदौर के राजवाड़ा में कांग्रेसियों ने किया शुद्धिकरण

- मंत्रोच्चार के साथ परिसर में गंगाजल छिड़का, बोले- सेना का अपमान करने वाले मंत्री ने किया अपवित्र

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस ने आज राजवाड़ा पर शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में देश की सेना का अपमान करने वाले उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राजवाड़ा को अपवित्र किया है। इसी कारण पूरे परिसर का गंगाजल से शुद्धिकरण करवाया गया। पंडित विशाल चतुर्वेदी द्वारा पवित्रीकरण और मंत्रोच्चार के साथ यह प्रक्रिया पूरी की गई। हालांकि, कांग्रेस के एक धड़े का कहना है कि देवेंद्र यादव के पास कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए कैबिनेट बैठक के दो दिन बाद वह इस तरह का प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्या होलकर के मूल्यों और आदर्शों को लेकर भाजपा द्वारा कही गई बातें उनके न्यायप्रिय और नैतिक परंपराओं का अपमान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताकर देश की सेना का अपमान किया है। इसी कारण राजवाड़ा परिसर का शुद्धिकरण किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ कर राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। यादव ने कहा कि मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। माफी न मांगने के बावजूद भाजपा उन्हें संरक्षण दे रही है। वहीं, उपमुख्यमंत्री की टिप्पणी से भाजपा की सोच और चरित्र उजागर हुआ है। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।

कैबिनेट को बना दिया इवेंट: देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कैबिनेट बैठक को भाजपा सरकार ने एक इवेंट की तरह पेश किया। बैठक के दौरान राजवाड़ा के आसपास की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया, जबकि सामने स्थित शराब की दुकान को खुला रखा गया। उन्होंने कहा कि कर्ज में डूबी सरकार ने इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च कर जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद किया। इंदौर में सड़कों की बदहाल स्थिति, धूल-धुएं और बिजली कटौती से जनता परेशान है। नशे और अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भय और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके बावजूद सरकार ने राजसी वैभव के साथ खुद का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मां अहिल्या देवी के नाम पर सरकार ने दिखावा किया, जबकि असली समस्याओं की अनदेखी की गई। भाजपा सांसद और कलेक्टर ने यह घोषणा की थी कि राजवाड़ा परिसर की सजावट दो दिन तक नहीं हटाई जाएगी, लेकिन यह भी केवल दिखावा साबित हुआ।

कोरोना ड्यूटी के दौरान एएसआई की मौत

- सरकार ने नहीं माना 'कोरोना वॉरियर', हाई कोर्ट ने दिया 50 लाख मुआवजे का आदेश

इंदौर (एजेंसी)। कोरोना की पहली लहर के दौरान ड्यूटी में तैनात देवास के एएसआई डेनियल भाभर (47) की संक्रमण से मौत हो गई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने उन्हें कोरोना वॉरियर मानने से इनकार करते हुए मुआवजे की राशि नहीं दी। परिवार ने हाई कोर्ट की शरण ली, जहां चार महीने चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को 45 दिनों में 50 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। डेनियल भाभर की तैनाती उस दौरान बैंक नोट

प्रेस और बाद में अमलतास अस्पताल (बांगर) में थी। संक्रमण की चपेट में आने के बाद 1 मई 2021 को उनकी मौत हो गई। निधन के बाद कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। वे अपने पीछे पत्नी मीना, दो बेटे और एक बेटी को छोड़ गए।

प्रशासन ने कहा- स्वास्थ्य विभाग में नहीं थे, पात्र नहीं: डेनियल की पत्नी मीना भाभर ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। लेकिन 29 नवंबर 2023 को जिला प्रशासन ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वे कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की धारा 3.1 में शामिल नहीं होते, क्योंकि वे स्वास्थ्य विभाग से नहीं थे। प्रशासन का तर्क था कि योजना के लाभ केवल डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को मिलते हैं, न कि पुलिसकर्मियों को।

एडवोकेट ने कोर्ट में पेश किए पुख्ता दस्तावेज: मीना भाभर ने अपने वकील यशपाल राठौर के जरिए 7 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

ऐसा बनेगा इंदौर का रणजीत लोक

7 करोड़ से संवरेगा 135 साल पुराना हनुमान मंदिर; रामायण-सुंदरकांड की झलक मिलेगी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर का कायापलट होने जा रहा है। यहां रणजीत लोक बनाकर मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर कुल 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्लान तैयार हो चुका है, टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। मंदिर के पुजारी पं. दीपेश व्यास ने कहा- रणजीत हनुमान मंदिर 135 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहां इंदौर ही नहीं, आस-पास के जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर प्रशासक एनएस राजपूत ने बताया कि रणजीत लोक तैयार होने के बाद श्रद्धालु मंदिर के पास बने बड़े मैदान से प्रवेश करेंगे। वहां से एक पाथ-वे के माध्यम से छोटी पार्किंग तक पहुंचेंगे। पाथ-वे में जिग-जैग पैटर्न पर रेलिंग लगाई जाएंगी। इनकी संख्या भीड़ के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद श्रद्धालु दत्त मंदिर से होते हुए दर्शन की मुख्य लाइन में पहुंचेंगे। भगवान के दर्शन कर वहीं से वापस बाहर निकलेंगे। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर का 7 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

पाथ-वे की दीवारों पर रामायण और सुंदरकांड की झलक: मंदिर प्रशासक राजपूत ने बताया- यहां सभी तरह के मौसम के मुताबिक व्यवस्थाएं जुटाई जाएंगी ताकि सर्दी, गर्मी और बारिश में भक्तों को परेशानी न हो। बैठने के लिए नई बेंच लगेंगी। बाउंड्रीवाल भी बनाई जाएगी। 25 फीट का पाथ-वे बनेगा, इसकी दीवारों पर पत्थरों से भगवान हनुमान से जुड़े दृश्य उकेरे जाएंगे। रामायण और सुंदरकांड को तस्वीरों में दर्शाया जाएगा।

छत पर कशीदाकारी, बाउंड्रीवॉल पर रंगबिरंगी रोशनी: रणजीत लोक की छत पर भी कशीदाकारी की जाएगी। बाउंड्रीवॉल पर रंगबिरंगी लाइटिंग लगेगी। यहां भी सुंदरकांड का चित्रण होगा। मंदिर का एक्सटेंशन 40 फीट आगे तक होगा। नया मुख्य द्वार बनेगा। शेड तैयार किए जाएंगे। मंदिर परिसर में ही पुलिस चौकी बनाई जाएगी। नया जूता स्टैंड, पेय जल की व्यवस्था की जाएगी। बेबी फीडिंग रूम और बुजुर्गों के लिए अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी।भक्त पाथ-वे के जरिए दर्शन करने जाएंगे। यहां एलईडी पर भगवान के लाइव दर्शन होंगे।

स्मार्ट सिटी संभाल रहा निर्माण की जिम्मेदारी: मंदिर प्रशासक राजपूत ने बताया- रणजीत लोक निर्माण की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी इंदौर स्मार्ट सिटी को दी गई है। इसके लिए मंदिर के फंड और दान की राशि का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इसका काम शुरू किया जा चुका है। पाथ-वे से होकर भक्त छोटी पार्किंग में पहुंचेंगे, जिग-जैग पैटर्न की लाइन से दर्शन करने आगे बढ़ेंगे।

पांचवीं पीढ़ी संभाल रही पूजा-अर्चना का काम

वर्तमान पुजारी पं. दीपेश व्यास के परदादा स्व. पं. भोलाराम व्यास इस मंदिर के संस्थापक पुजारी थे। उनकी पांचवीं पीढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना कर रही है। व्यास ने कहा- शुरुआत में बाबा रणजीत टीन से बने शेड में विराजमान थे। 1960 में गार्डर-फर्शी से पक्का निर्माण किया गया। 1992 में आरसीसी छत डाली गई। व्यास के अनुसार, होलकर राजा जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो यहां पूजा-हवन करते थे। विजय की कामना के साथ यहां आते और फिर युद्ध के लिए जाते थे इसलिए मंदिर का नाम रणजीत हनुमान पड़ा।

उन्होंने कहा- पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर यहां रणजीत अष्टमी मनाई जाती है। सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाती है। दिनभर पूजा-अर्चना और विशेष आरती की जाती है। 21 लाख रुपए के रथ पर सवार होकर रणजीत हनुमान नगर भ्रमण करते हैं।

हल्की बारिश के बाद सुबह मौसम साफ

- मई में रिकॉर्ड बारिश
- 22 दिन में 6.25 इंच, आज भी तेज हवाएं और बारिश की संभावना

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में मई माह में अभी भी बीच-बीच में बारिश का दौर जारी है। देर रात शहर के पश्चिम क्षेत्र में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि यह कुछ मिनट तक ही हुई जबकि पूर्वी हिस्से में इसका असर नहीं था। अभी तक मई के 22 दिनों में सवा छह इंच बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले दो तीनों में तेज हवा और बारिश के आसार जताए हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया-इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ एक्टिव है, जो मध्यप्रदेश से होकर गुजर रही है। इसी वजह से मौसम में बदलाव आया है और अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। दो दिनों से दिन का तापमान 36 डिग्री से ज्यादा रात का तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को सुबह से मौसम साफ था लेकिन दिनभर में उमस में काफी परेशान किया। फिर रात 11.30 बजे मौसम बदला। फिर बादल छाए और कुछ हिस्सों में कुछेक मिनट हल्की बारिश हुई। मई में अब तक 162.5 मिमी (सवा छह इंच से ज्यादा) बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम पर ठग रहे थे पैसा

18 महीने में 50 प्रतिशत मुनाफे का झांसा, इंदौर पुलिस ने पकड़ा फर्जी इन्वेस्टमेंट नेटवर्क

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में पलासिया पुलिस ने फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसका साथी ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन निवेश करवा रहे थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ मोबाइल एप बनवाया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए

प्रचार कर लोगों को जाल में फंसाया। एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने बैकुंठधाम कॉलोनी स्थित अनोमल स्पेस की फ्लैट नंबर 202 पर कार्रवाई की। यहां आरोपी सिद्धार्थ मालवीय, अपने साथी उमेश सहाय के साथ मिलकर ऑफिस चला रहा था। ऑफिस में युवक-युवतियों से टेली कॉलिंग कराई जा रही थी, जिनके जरिए लोगों से निवेश के लिए संपर्क किया जाता था।

ईवी प्रोजेक्ट के नाम पर 40-50 प्रतिशत मुनाफे का लालच: आरोपियों ने डॉट ईवी नाम से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रखी थी। कॉलर्स लोगों को बताते थे कि उनकी कंपनी की सरकार से टाय-अप है और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रोजेक्ट है। निवेश करने पर 18 महीने बाद 40 से 50 फीसदी तक का लाभ देने का दावा किया जाता था। निवेश की शुरुआत 4,600 रुपए की पहली किश्त से होती थी, और योजना में 50 हजार रुपए तक निवेश का विकल्प दिया गया था। इस पूरे काम के लिए एक मोबाइल एप भी बनाया गया था, जिसे प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन चला कर लोगों को लुभाया जा रहा था।

ऑफिस से मोबाइल, लैपटॉप जब्त; साथी की तलाश: पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 8 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। मामले में आरोपी का साथी उमेश सहाय फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले टीआई मॉल के पास ऑफिस चला रहा था और हाल ही में पलासिया में शिफ्ट हुआ था। अब यह जांच की जा रही है कि कितने लोगों से और कितनी राशि उनके खातों में ट्रांसफर कराई गई है। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

शूटिंग कोच पर दो और एफआईआर

महिला वकील को धमकी देकर किया रेप; कर्मचारी से अश्लील बातें की, अपशब्द कहे

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में रेप और अश्लील हरकतें करने के आरोपी ड्रीम ओलिपिंक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान के खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गई हैं। अन्नपूर्णा थाने में एक महिला वकील ने रेप और दूसरी महिला ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। दोनों गुरुवार को थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। पहली पीड़िता पेशे से वकील है और एलएलएम की पढ़ाई कर रही है। दूसरी शिकायतकर्ता आदिवासी है। वह मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में नौकरी करती थी। पुलिस ने महिला वकील की शिकायत पर रेप, धमकी देने और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज किया है, वहीं दूसरी महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और जातिगत टिप्पणी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

मोहसिन खान

धमकी देकर किया रेप, बदनामी का डर दिखाया: महिला वकील ने बताया कि वह सुदामा नगर की रहने वाली है। फरवरी 2021 में शूटिंग सीखने के लिए ड्रीम ओलिपिंक एकेडमी पहुंची थी। कोच मोहसिन खान कोचिंग के नीचे वाले फ्लैट में रहता था। जुलाई 2022 में एक दिन मोहसिन ने उसे कॉल कर फ्लैट में बुलाया। कहा कि एक प्रतियोगिता के लिए जरूरी बात करनी है। फ्लैट के भीतर मोहसिन ने उसे गले लगा लिया। विरोध करने पर धमकाया, चुप रहो। जैसा मैं कहूं, वैसा करो। यहां कोई नहीं आने वाला है। इसके बाद जबरन उसके साथ संबंध बनाए। जब पीड़िता रोने लगी तो आरोपी ने धमकी दी, अगर किसी को बताया तो बदनामी तुम्हारी होगी। तुमसे शादी कौन करेगा?

शादी के बाद ब्लैकमेल किया, पति को बताने की धमकी दी: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि डर के चलते वह चुप रही। इसी का फायदा उठाकर दिसंबर 2023 तक मोहसिन ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान पीड़िता की शादी हो गई और अप्रैल 2024 में वह इंदौर से बाहर चली गई।

जॉब दिलाने के नाम पर 3 लाख की ठगी

सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर लिए थे रुपए; डायरेक्टर पर केस दर्ज, चेक भी निकला बाउंस

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में जॉब दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी के मामले में हीरानगर पुलिस ने एक निजी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पीड़ित से रकम ली और न नौकरी दी, न ही पैसे लौटाए। बाद में दिए गए चेक की बैंक ने पेमेंट रोक दी, जिससे मामला सामने आया।

पुलिस के अनुसार, भवानी नगर निवासी प्रेम कुमार ने शिकायत में बताया कि जुलाई 2024 में उनकी पहचान सरिता नामक महिला के जरिए सचिन तिवारी से हुई थी। सरिता ने बताया था कि सचिन को अपनी कंपनी सर्च इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर्मचारियों की जरूरत है। बातचीत में सचिन ने खुद को डायरेक्टर बताया और कहा कि उनकी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का काम करती है।

सचिन ने प्रेम को वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया, जिसमें 20 हजार रुपए सैलरी और 7 हजार रुपए इंसेंटिव देने की बात कही। साथ ही कहा कि नौकरी के लिए 3 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होंगे, जिसके बदले लैपटॉप और जरूरी सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे। प्रेम ने एचडीएफसी बैंक के जरिए जुलाई 2024 में आरोपी के खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके बाद न तो उसे नौकरी दी गई और न ही कोई ट्रेनिंग। जब प्रेम ने बार-बार संपर्क किया तो आरोपी टालमटोल करता रहा।

चेक भी बाउंस हो गया

6 दिसंबर 2024 को प्रेम कुमार आरोपी के ऑफिस गया और पैसे वापस मांगे। तब आरोपी ने उसे एक चेक थमा दिया, लेकिन जब प्रेम ने वह चेक बैंक में लगाया तो स्टॉप पेमेंट का हवाला देकर बैंक ने भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी को कई बार कॉल किए, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया।

थक-हारकर प्रेम कुमार ने हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया निवासी सचिन तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

इंदौर के दतोदा गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ

रालामंडल वन विभाग की टीम ने बचाया; पिंजरे में रखकर कुछ समय करेंगे निगरानी

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर जिले में कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग ने शुक्रवार को बाहर निकाल लिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) योगेश यादव ने बताया कि इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर दतोदा गांव के एक खेत के कुएं में तेंदुआ गिर गया था और ग्रामीणों की भीड़ इसके आस-पास जमा हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने पर बचाव दल भेजकर तेंदुए को पानी से भरे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेंजर योगेश यादव ने बताया- तेंदुए को इंदौर के चिड़ियाघर लाकर पिंजरे में कुछ समय के लिए निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। गर्मी बढ़ने पर तेंदुए भोजन और पानी की तलाश में जंगल से

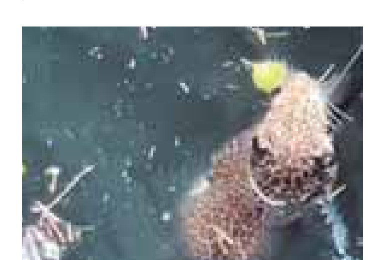

भटक कर मानवीय बसाहटों के पास आ जाते हैं।

तेंदुए को नहीं आई कोई चोट: जू क्यूरेटर निहार पारूलेकर ने बताया कि वन विभाग ने शुक्रवार को एक तेंदुए का रेस्क्यू किया है। वे उसे लेकर आए थे, वह फीमेल है। जिस कुएं में तेंदुए गिरा था, वह बहुत गहरा बताया जा रहा है।

भोपाल-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन इंदौर से चलाने की मांग

- सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री को पत्र लिखा; 4 ट्रेनों में सालभर वेटिंग, जून में शुरू होने की उम्मीद

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर भोपाल से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, तो उसे इंदौर से शुरू किया जाए ताकि इंदौर के यात्रियों को भी फायदा मिल सके। उन्होंने पत्र में लिखा, इंदौर रेलवे के मुख्य मार्ग पर नहीं है, इसलिए यहां के यात्रियों को

काफी परेशानी होती है। अगर प्रस्तावित ट्रेन को इंदौर से चलाया जाए, तो यह बहुत उपयोगी होगा।

डेली यात्री संगठन ने भी की थी मांग: कुछ दिन पहले इंदौर के डेली रूटीन यात्रियों के संगठन ने भी यही मांग उठाई थी। सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा कि रेलवे को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इंदौर से लखनऊ के लिए सिर्फ चार ट्रेनें: इस समय इंदौर से लखनऊ के बीच केवल चार ट्रेनें चलती हैं। इनमें दो ट्रेनें- महाकाल एक्सप्रेस और इंदौर एक्सप्रेस- सप्ताह में दो बार चलती हैं। वहीं डॉ. अंबेडकर नगर-कामाख्या एक्सप्रेस और इंदौर-पटना एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार चलती हैं। इन ट्रेनों में यात्रा का समय 15 से 16 घंटे तक होता है। ट्रेनें कम होने की वजह से हर समय वेटिंग टिकट रहती है। त्योहारों के समय वेटिंग 300 से ज्यादा हो जाती है।

वंदे भारत ट्रेन से सफर तेज और आरामदायक होगा: रेलवे भोपाल से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो जून के अंत तक शुरू हो सकती है। यात्री चाहते हैं कि यह ट्रेन इंदौर से चलाई जाए। इससे इंदौर-भोपाल का सफर भी तेज होगा और लखनऊ, बीना, झांसी और कानपुर जैसे शहरों से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन में 564 सीटें होती हैं और इसका किराया थोड़ा प्रीमियम होता है, जिससे सीटों की ज्यादा मांग नहीं होती और कन्फर्म टिकट मिलना आसान होता है। अभी इंदौर से लखनऊ की चारों ट्रेनों में 100 से 150 वेटिंग चल रही है। अगर वंदे भारत ट्रेन शुरू होती है, तो यात्रियों को एक नया और तेज़ विकल्प मिल जाएगा, जिसमें 10 से 12 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा।

संपादकीय

अब पूर्ण साक्षर मिजोरम

सुदूर पूर्वोत्तर के छोटे से सीमावर्ती राज्य मिजोरम का पूर्ण साक्षर बनना अपने आप में गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इस आदिवासी बहुल राज्य में अब एक भी अनपढ़ नहीं बचा, इसका ऐलान खुद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसके पहले देश के सर्वाधिक साक्षर राज्य का ताज 93.91 प्रतिशत साक्षरता के साथ बरसों तक केरल के सिर पर रहा। लेकिन अब यह सम्मान मिजोरम ने छीन लिया है। वहां साक्षरता दर 96 प्रतिशत हो चुकी है, जो पूर्ण साक्षरता के बराबर ही है। मिजोरम की कुल आबादी 14 लाख है। राज्य में 11 जिले हैं। मिजोरम ने यह कामयाबी 'उल्लास (नवभारत साक्षरता कार्यक्रम) के तहत हासिल की। अब मिजोरम का हर वयस्क व्यक्ति पढ़ने लिखने मे सक्षम है। वैसे तो मिजोरम की इस कामयाबी के पीछे कई कारक हैं। लेकिन वहां साक्षरता की नींव पहले से मजबूत थी। 2011 की जनगणना में मिजोरम की साक्षरता दर 91.33 प्रतिशत थी, जो देश में तीसरे स्थान पर थी। उल्लास योजना के तहत 2023 में पूरे राज्य में सर्वे किया गया। इसमें 3026 निरक्षर लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 1,692 ने रोजाना पढ़ाई शुरू की। इसके बाद राज्य की साक्षरता दर 98.20 प्रतिशत तक जा पहुंची। सरकार ने 292 स्वयंसेवक तैयार किए, जिनमें छात्र, शिक्षक, एक्सपर्ट और क्लस्टर रिसोर्स को-ऑर्डिनेटर शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर सबको पढ़ाया। गौरतलब है कि लद्दाख पहले ही इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुका है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ललदुहोमा के अनुसार 292 स्वयंसेवक शिक्षकों के कारण यह संभव हुआ है। इस टीम ने जो सर्वे किया, वो चार सवालों पर फोकस था। जैसे कि क्या आप अपना नाम लिख सकते हैं? क्या आप अखबार पढ़ सकते हैं? क्या आप गिनती गिन सकते हैं या पैसे का हिसाब कर सकते हैं? तथा क्या आप कभी स्कूल गए हैं? जो इन सवालों के जवाब नहीं दे सके, उन पर ध्यान केन्द्रित कर उन्हें साक्षर बनाया गया। इस अभियान में गांव प्रमुखों ने भी अहम भूमिका निभाई। लोगों में कर्तव्य बोध और शिक्षा बोध जागृत किया। पढ़ने वालों को कॉपी, पेन, स्लेट, पुस्तिकाएं आदि मुफ्त दी गईं। इसी के साथ विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं, इसी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसकी भी निगरानी की जा रही थी कि स्वयंसेवक शिक्षक ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं। विद्यार्थियों के 6 माह बाद परीक्षा भी ली गई। यूं तो भारत में साक्षरता लगातार बढ़ ही रही है। शिक्षित होने के लाभ तथा शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता ही देश में साक्षरता वृद्धि का प्रमुख कारण है। दूसरे, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ रहा है, इसका कारण भी मां बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। मप्र जैसे राज्य में तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में बेटियो की शिक्षा मुफ्ती ही है। इसका भी असर पड़ता है। मिजोरम जैसे प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर राज्य का इस मुकाम पर पहुंचना काफी मायने रखता है। पूर्ण साक्षर होने के मिजोरम को कई लाभ होंगे।यह राज्य पर्यटन की दृष्टि से देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्य की तुलना में पीछे है। अधिकांश देशवासी मिजोरम को रंगबिरंगी कपड़े पहनने वाले आदिवासी प्रदेश के रूप में ही जानते हैं। लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल रही है। लड़के लड़कियों में पढ़ने की भूख बढ़ी हैं। पढ़ाई करने काम करने वालों में लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है। वैसे आजादी के बाद 77 सालों में देश में अभी भी निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ी ही है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। मिजोरम ने पूर्ण साक्षर होकर पूरे देश को नई दिशा दिखाई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने जासूस यूट्यूबर की चुनौती

नजरिया

संदीप सृजन

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

पूछताछ में ज्योति ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ 'राष्ट्र-विरोधी' जानकारी साझा की थी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश की गई, जिसे अब जांच एजेंसियां संदिग्ध मान रही हैं। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनके यूट्यूब चैनल 'ट्रैवल विद जो' से होने वाली आय का अनुमान लगाया गया है। यूट्यूब विज्ञापनों से प्रति 1,000 व्यूज पर 1-3 डॉलर (80-240 रुपये) की कमाई होती है।

ज्योति मल्होत्रा का मामला एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका भंडाफोड़ हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद हुआ। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में सक्रिय जासूसों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हरियाणा और पंजाब से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज्योति मल्होत्रा प्रमुख हैं। अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों में गजाला, यामीन मोहम्मद, और देविंदर सिंह ढिल्लो शामिल हैं। ये सभी कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी, अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश, के संपर्क में थे।

ज्योति की गिरफ्तारी से पहले पंजाब पुलिस ने मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। गजाला का काम दानिश से पैसे लेकर जासूसों तक पहुंचाना था, जबकि यामीन हवाला और अन्य माध्यमों से धनराशि ट्रांसफर करने में शामिल था। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने ज्योति और अन्य जासूसों के नाम उजागर किए। हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार देविंदर सिंह ढिल्लो ने 2024 में गुरु नानक जयंती के अवसर पर पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसे हनी ट्रैप में फंसाकर पटियाला कैंट की तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए मजबूर किया गया।

ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान कनेक्शन 2023 में शुरू हुआ, जब वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीजा लेने दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन गई थीं। वहां उनकी मुलाकात अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई, जो पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत एक अधिकारी था। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया और उनके ठहरने और घूमने की व्यवस्था की। ज्योति ने 2023 और 2024 में तीन बार पाकिस्तान की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात दानिश के परिचित अली अहवान, शाकिर, और राणा शहबाज जैसे व्यक्तियों से हुई। इनमें से कुछ लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे।

ज्योति ने अपने मोबाइल में शाकिर का नंबर 'जट रंधावा' के नाम से सेव किया था ताकि किसी को शक न हो। वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन लोगों के साथ संपर्क में थी। पूछताछ में ज्योति ने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ 'राष्ट्र-विरोधी' जानकारी साझा की थी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश की गई, जिसे अब जांच एजेंसियां संदिग्ध मान रही हैं।

ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनके यूट्यूब चैनल 'ट्रैवल विद जो' से होने वाली आय का अनुमान लगाया गया है। यूट्यूब विज्ञापनों से प्रति 1,000 व्यूज पर 1-3 डॉलर (80-240 रुपये) की कमाई होती है। यदि उनके वीडियो पर औसतन 50,000 व्यूज आते थे और वह महीने में 10 वीडियो पोस्ट करती थीं, तो उनकी मासिक आय 40,000 से 1.2 लाख रुपये के बीच हो सकती थी। इसके अलावा, ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप से भी उनकी

कमाई होती थी। एक अनुमान के अनुसार, वह प्रति ब्रांड पोस्ट 20,000 से 50,000 रुपये चार्ज करती थीं, जिससे उनकी मासिक आय 80,000 से 2.7 लाख रुपये तक हो सकती थी।

ज्योति की कुल नेटवर्थ 15 से 40 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है, जो उनकी आय, खर्च, और जीवनशैली पर निर्भर करता है। हालांकि, पुलिस जांच में यह सामने आया कि उनकी आय उनके खर्चों से कहीं अधिक थी, जिसने विदेशी फंडिंग की संभावना को जन्म दिया। उनके बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें पाकिस्तान या अन्य स्रोतों से धन प्राप्त हो रहा था।

ज्योति मल्होत्रा का मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ज्योति को अपनी संपत्ति के रूप में विकसित कर रही थी। वह अन्य यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के संपर्क में थी, जो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यह एक तरह का 'सूचना युद्ध' है, जिसमें पाकिस्तान सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच शुरू की है, जिसमें कई पाकिस्तानी नंबर कोड नेम के तहत सेव मिले हैं। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच हो रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि उन्होंने 2023 से 2025 तक भारत में किन राज्यों और विदेशों में किन देशों की यात्रा की। खास तौर पर, उनकी पाकिस्तान यात्राओं के दौरान अली अहवान, शाकिर, और राणा शहबाज जैसे व्यक्तियों से मुलाकात की जांच हो रही है।

ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से जांच एजेंसियां हिसार पहुंचीं ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। यह मामला पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज की। भारत सरकार ने 13 मई, 2025 को पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को जासूसी के आरोप में देश से निष्कासित कर दिया था। दानिश इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो पैसे और हनी ट्रैप जैसे तरीकों से भारतीय नागरिकों को अपने जाल में फंसा रहा था।

पंजाब और हरियाणा में सक्रिय इस जासूसी नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ज्योति और अन्य जासूसों ने किन-किन जानकारियों को साझा किया और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना जा रहा है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी का रिसाव सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। ज्योति मल्होत्रा का मामला सामाजिक और नैतिक सवाल भी उठाता है। एक तरफ, वह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सांस्कृतिक एकता और सद्भाव का संदेश दे रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ, उन पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। उनके वीडियो में पाकिस्तान की तारीफ और दोनों देशों के बीच दोस्ती की बातें थीं, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था।

ज्योति के पिता, हरिस कुमार, ने उनकी गिरफ्तारी पर बयान दिया कि उनकी बेटी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि ज्योति केवल कंटेंट क्रिएशन के लिए यात्राएं करती थीं और उनकी सभी यात्राएं अनुमति के साथ थीं। हालांकि, जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत होने का दावा है, जिसमें उनके डिवाइसों से बरामद डेटा और उनकी पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत शामिल है।

ज्योति मल्होत्रा का मामला यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन या जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह जासूसी और सूचना युद्ध का एक नया हथियार बन गया है। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर, जो लाखों लोगों तक अपनी पहुंच रखते हैं, संवेदनशील जानकारी साझा करने का एक आसान जरिया बन सकते हैं। ज्योति जैसे लोग, जो अपनी यात्राओं और वीडियो के माध्यम से एक सकारात्मक छवि बनाते हैं, आसानी से लोगों का भरोसा जीत सकते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने इसे 'एक तरह का युद्ध' करार दिया, जिसमें पाकिस्तान प्रभावशाली लोगों को भर्ती करके अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ज्योति का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल जानकारी साझा की जा सकती है, बल्कि इसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

ज्योति मल्होत्रा और अन्य जासूसों की गिरफ्तारी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने एक नई चुनौती पेश की है। यह मामला न केवल जासूसी नेटवर्क के खतरे को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि डिजिटल युग में सूचना युद्ध कितना जटिल और खतरनाक हो सकता है। ज्योति का मामला एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और समय पर कार्रवाई ने इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है कि ऐसे कितने और लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह मामला न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक सबक है कि डिजिटल दुनिया में सावधानी और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है।

गैर-परमाणु अक्षय ऊर्जा उत्पादन हो प्राथमिकता

ऊर्जा नीति

राजकुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

भारत सरकार संसद के आगामी सत्र में परमाणु ऊर्जा संबंधी अधिनियमों में संशोधन करने जा रही है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'निजी ऑपरेटरों को अनुमति देने और उनकी देनदारी सीमित करने' का यह कदम उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को भारत में परमाणु उपकरण बनाने और डिजाइन करने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' (यूपीए) सरकार ने इसके लिए जो 'सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010' बनाया था, उसकी शर्तें देशों के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती थीं, कंपनियों को ज़िम्मेदार बनाती थीं। इसी तरह एक दूसरा क़ानून 'एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962' भी है जिसके तहत केन्द्र सरकार 'परमाणु ऊर्जा केन्द्रों' का विकास और संचालन करती है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जल्द-से-जल्द परमाणु दायित्व के बिल को संसद में पारित करवाना चाहते थे, मगर संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दलों तथा अन्य नागरिक संगठनों के विरोध और उनकी सरकार के डांवाडोल होने के कारण उन्हें उसे वापस लेना पड़ा था। इस बिल के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना होने पर सप्लायर को किसी भी क्षतिपूर्ति से मुक्त रखा गया था। बाद में विपक्षी दलों की मांग के अनुरूप बिल में बदलाव किए जाने पर 'सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डेमेज एक्ट 2010' संसद से पारित हुआ था।

इस अधिनियम के तहत फिलहाल घरेलू निजी कम्पनियों की ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी होती है, परन्तु 'नीति आयोग' की ओर से गठित सरकारी समिति ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर लगी पाबंदी हटाने की सिफारिश की है। समिति ने परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में विदेशी कम्पनियों को शामिल करने के लिए अधिनियम के साथ 'विदेशी निवेश अधिनियमों' में भी बदलाव की सिफारिश की है।

गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए 2008 के समझौते के तहत परमाणु प्रौद्योगिकी सामग्रियों के आयात की अनुमति दी थी और निजी कम्पनियों को भारतीय परमाणु बाजार में प्रवेश करने का रास्ता खोला था। यह समझौता अमेरिका के 'परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954' की 'धारा 123' के तहत किया गया था जिसे '123 समझौता' कहा गया था। इस समझौते को लेकर देशभर में गंभीर सवाल उठे थे।

प्रस्तावित बदलाव का संकेत 2022 में भारत-अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच वाशिंगटन की द्विपक्षीय वार्ता के समय ही मिल गया था, जब अमेरिकी कम्पनी ने भारत में 60 हजार करोड़ रुपए की लागत से छह परमाणु रिएक्टर लगाने और भारत के घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए 'लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर' (एसएमआर) तकनीक के विकास पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए निवेश की इच्छा जाहिर की थी। 'एसएमआर' ऐसे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो केवल 10 से 300 मेगावाट बिजली उत्पादित करते हैं। इनके मॉड्यूलर डिजाइन और छोटे आकार के चलते जरूरत के मुताबिक एक ही साइट पर इनकी कई इकाइयां लगाई जा सकती हैं। इसको लेकर उस समय 'न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया' और 'वाशिंगटन इलेक्ट्रिक कंपनी' के बीच 2022 में बातचीत अंतिम चरण में थी।

भारत चरणबद्ध तरीके से परमाणु ऊर्जा में 49 प्रतिशत तक 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (एफडीआई) की अनुमति दे सकता है। सरकार शुरुआती चरण में केवल 26 प्रतिशत तक की अनुमति दे सकती है और समीक्षा के बाद इसे बढ़ा सकती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2035 तक परमाणु ऊर्जा को वर्तमान 8 गीगावाट से बढ़ाकर 40 गीगावाट करने के लिए निजी क्षेत्र को खोलने की योजना बनाई है। भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपनी अपील दोहराई है कि वे भारत के मौजूदा कानूनों को कमजोर करने के लिए अमेरिका और अन्य परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के दबाव में न आएं, जैसा कि वित्तमंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में संकेत दिया है।

सवाल उठता है कि परमाणु क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियां भारत क्यों आना चाहती हैं? दरअसल आजकल परमाणु बिजली उद्योग में जबरदस्त मंदी है, इसलिए अमेरिका, फ्रांस और रूस आदि देशों की कम्पनियां भारत में इसके ठेके और आर्डर पाने के लिए बेचैन हैं। वर्ष 2017 में जारी 'विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट' (वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट) में बताया गया था कि पिछले चार सालों में दुनियाभर में निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 2013 तक वैश्विक स्तर पर 68 रिएक्टरों का निर्माण कार्य चल रहा था, वहीं 2017 में निर्माणाधीन रिएक्टरों की संख्या 53 हो चुकी थी।

'भोपाल गैस त्रासदी' के पीड़ित आज तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में विदेशी कंपनियों को कड़े कानूनों से छूट देकर हम अपने नागरिकों के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। अमेरिका की परमाणु कंपनियों को यह छूट भारत के लिए भारी पड़ सकती है। भारत में निवेश से मोटा मुनाफ़ा कमाने वाली परमाणु कंपनियों को उनके दायित्व से कैसे छूट मिल सकती है? भारत में व्यापार कीजिए, मुनाफ़ा अमेरिका ले जाइए। अगर कोई गड़बड़ी हो तो हाथ झाड़कर खड़े हो जाइए। सवाल पूछने वालों पर कंपनी उल्टे मुक़दमे क़ायम कर देगी, क्योंकि हमारा क़ानून उनके लिहाज़ से तैयार किया जा रहा है।

परमाणु क्षेत्र के निजीकरण, 'एसएमआर' के अनुसंधान और विकास के लिए बड़े बजटीय आबंटन करना परमाणु विस्तारवाद की ओर बढ़ता कदम है। एक 'एसएमआर' अपने 60 वर्षों के अपेक्षित जीवन में, अपशिष्ट के रूप में लगभग 1,800 टन 'व्यय ईंधन' उत्पन्न करेगा। चुने गए स्थल को बहुत लंबी अवधि में 'व्यय ईंधन' के सुरक्षित भंडारण के लिए प्रावधान करना होगा। कानूनी प्रावधानों में यह सुनिश्चित करना होगा कि निजी पक्षों के स्वामित्व वाली साइटें विनियामक नियंत्रण में रहें।

डिज़ाइन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में प्रारंभिक रूप से खर्च किए गए ईंधन और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकताओं को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी अपशिष्टों के निपटान के लिए एक निश्चित मार्ग है? इसलिए 'एसएमआर' के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, उत्पादन और मॉड्यूल असेंबली के सभी चरणों में तथा स्टार्ट-अप और संचालन के लिए, उत्पादन और सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए, विनियामक निरीक्षण और नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता होगी।

केन्द्र सरकार ने 'परमाणु ऊर्जा मिशन' के लिए 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। यह राशि 'एसएमआर' के अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित की गई है। इसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम-से-कम पांच स्वदेशी 'एसएमआर' विकसित करना है। सरकार परमाणु विकिरण के दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभावों को समझे और इसके बजाय विकेंद्रीकृत, न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभावों वाले और सामाजिक समानता और वित्तीय स्थिरता के सिद्धांतों को बनाए रखने वाले 'गैर-परमाणु अक्षय ऊर्जा' उत्पादन को प्राथमिकता दे। (सप्रेस)

1952 से अब तक आदिवासियों का निरंतर अहिंसक संघर्ष

नगरी-सिहावा का आंदोलन

जयंत सिंह तोमर

लेखक स्वतंत्र अध्येता हैं।

तेहत्तर साल बीत गये, पांच पीढ़ियां खप गयीं, तब जाकर छत्तीसगढ़ में नगरी- सिहावा के आंदोलन का एक चक्र पूरा हुआ। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती हैं, 'पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है/ जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है।' नक्सलवाद के लाल गलियारे के बीच नगरी सिहावा अहिंसा का एक टापू है। 1952 से अब तक यहां के आदिवासियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भूमि अधिकारों के लिए निरंतर अहिंसक संघर्ष किया। जब नया छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा था तब लंबे समय तक भूखे प्यासे रहकर हजारों आदिवासी ने राजधानी रायपुर में डेरा डाले थे और देश की आजादी के बाद से चल रहे इस आंदोलन को गति दे रहे थे।

डॉ. राममनोहर लोहिया सन् 1952 में छत्तीसगढ़ अंचल में धमतरी जिले के उमरादेहान गांव में आये थे। यहीं से उन्होंने जंगलों में बसे आदिवासियों के भूमि-अधिकार का मुद्दा उठाया था। आज भारत में आदिवासियों को आजीविका के लिए जमीन मिली है, वनग्रामों को राजस्व ग्राम जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। इन सबके मूल में नगरी सिहावा का ही आंदोलन है। इसी उमरादेहान गांव में आगामी 24 मई को डॉ राममनोहर लोहिया की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। आदिवासियों ने एक एक मुट्ठी अनाज हर घर से लेकर प्रतिमा तैयार कराई है। लोहिया जी जब तक रहे यानी 1967 तक, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1977 के बाद इसकी बागडोर देश के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने सम्हाली। उनका समूचा जीवन संघर्ष और आंदोलनों में बीता। आपातकाल में उन्नीस महीने जेल में रहे।

अनेक संघर्षों के बाद सन् 1990 आते आते नगरी सिहावा के अठारह में से तेरह गांवों के आदिवासियों को जमीन का पट्टा मिल गया, पर पांच गांव फिर भी छूट गये। इससे पांच साल पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहां दुगली में आये थे, आदिवासियों की झोपड़ी के सामने चारपाई पर बैठे थे पर आदिवासियों को उनके हक बिना पदयात्रा, प्रदर्शन व अनशन के नहीं मिले। रघु ठाकुर ने जाकर आदिवासियों के इस आंदोलन को तेज किया। उसी दुगली से रायपुर तक 120 किमी की पदयात्रा की जिसमें हजारों आदिवासी आदमी - औरतें और बच्चे पैदल चले थे। इन आन्दोलनों में पत्रकार मधुकर खेर, गोविन्दलाल वोरा, सत्यनारायण शर्मा, नारवानी जी व रमेश वल्यानी का बड़ा सहयोग मिला। सरकार के मंत्रियों ने आकर आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित कराया, पर वादा पूरा नहीं किया। रघु जी को फिर रायपुर आकर अम्बेडकर चौक पर अनशन शुरू करना पड़ा। सांसद जार्ज फर्नांडीज और शरद यादव ने आकर गिरफ्तारियां दीं, मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर दोनों पक्ष में समझौते के कागज तैयार हुए। इसके तहत तय हुआ कि अट्ठारह गांवों के कब्जे की जमीन की जांच कराई जाएगी और निर्धारित नियम के तहत पट्टे दिए जायेंगे, जिन पांच गांवों को उजाड़ा गया है उन गांवों के लोगों की भी झोपड़ियों को दुरुस्त कराकर बसाया जायेगा, जमीन दी जायेगी। तेरह गांवों को तो पट्टा मिल गया, लेकिन यही पांच गांव को पट्टा मिलने में पच्चीस साल और लग गये। इस आंदोलन का इतिहास जब भी देश की जनता के सामने आयेगा सुखराम नागे, जुगलाल नागे, बिसाहूलाल साहू, रामू, बिसाहिन बाई, समरीनबाई, रामप्रसाद नेताम, गौड़ा राय, वंशी श्रीमाली, जालिम सिंह जैसे अनेक लोगों का संघर्ष सभी को प्रेरणा देगा।

इस आंदोलन के संदर्भ में यह बताना भी जरूरी है कि कुछ लोग सत्ता में रहते हुए भी समय पर कुछ नहीं कर पाये, कुछ ने समय का लाभ उठाकर अपने वैचारिक समर्थकों को उपकृत किया तो कुछ आदिवासियों को समाजवादी धारा से हटाकर अपने - अपनी राजनीतिक जमीन पुख्ता करने का प्रयास किया।नगरी सिहावा का तेहत्तर साल चला आंदोलन अभी थमा नहीं है। यह चिकित्सा और शिक्षा के मूल अधिकार की लड़ाई को आगे ले जायेगा। इस आंदोलन का कई कारणों से ऐतिहासिक महत्व है। नक्सली हिंसा से घिरे वनांचल में यह अहिंसा का टापू है। भारत का पहला वनग्राम सम्मेलन यहीं से शुरू हुआ। और , वन अधिकार कानून का जन्मदाता यही क्षेत्र है। यहां की महिलाओं की मुक्त भावना और संघर्ष के जज्बे से शेष भारत प्रेरणा ले सकता है।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नेताजी का कमाल

व्यंग्य

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

नेताजी ने अक्षर ज्ञान में क से कोयला पढ़ा था सो जीवन भर कोयले की दलाली में हाथ काले करते रहे। इस कारण कालिख से भी जन्म जन्मांतर के संबंध बन गये।बाद में कोशिशों के बाद भी छुड़ाये न छूटे। जो काजल नयनों की शोभा के काम आता था वो नेताजी के पूरे बदन को यहां तक कि चेहरे को भी शोभायमान करने लगा।उस पर भी उनकी कटारी सी आंखें सामने वाले को काट डालने का उपक्रम करतीं चीर कर रख देतीं।लोग उनके आगे बोलने से भी डरने लगे भले ही उनके पास अपने किसी ज़रूरी काम से आये हों।

नेताजी की वट-वृक्ष सी फैलती कटि के कारण उनकी कुर्सी और कमोड दोनों ऑर्डर पर बनने लगे।क्योंकि उनके हिसाब के तो बाजार में उपलब्ध ही न थे।ताक़त में भी वे किसी से कम न थे। क्रोध में हों तो सामने वाले को केवल एक कान पकड़ कर उठा दें।दूसरे दिन एक की तुलना में दूसरा कान तीन गुना देखकर सबको ज्ञात हो जाता कि भैयाजी कल ज़रूर नेताजी से मिले होंगे। कुछ ने तो उन्हें कुछ लोगों के कपड़े उतारकर उनका कचूमर बनाते देखा है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कुछ कम है।पर दूसरों के क्रियाकर्म में नेताजी का कौशल देखने लायक है इसे उनके घोर विरोधी भी स्वीकारने में देर नहीं करते।

लोग कीचड़ में कमल खिलाते हैं नेताजी काला सोना बना लेते हैं जिसे पीला करने में उन्हें देर नहीं लगती। उनसे जुड़े लोग कतार में खड़े रहते हैं उनकी चरण रज लेने के लिए ताकि बिना कठिनाई के दोनों हाथों से चांदी चमका सकें।

नेताजी में लाख बुराई हो पर एक अच्छाई है । कोई कितना भी आग्रह करे नेताजी कभी सार्वजनिक रूप से कंठ तर नहीं करते।इसके लिए उनके तीन चार सहयोगी रिज़र्व हैं। परमानेंट। उनसे पहले के जो जन प्रतिनिधि थे उन्हें तो शादी ब्याह में ही कोई टेबिल के नीचे डिस्पोज़ल गिलास में बनाकर दे दे तो दोनों हाथ लगाकर ले लेते थे।

कलाकार कठोर कपटी कायर कुकर्मी कुख्यात केंचुआ केकड़ा जैसे समयानुकूल विशेषण भी अलग-अलग समयों पर उनकी पूरी प्रतिभा को उघाड़ने में असमर्थ थे। क से बने बहुत से शब्द तो लोग डर के मारे बोलते ही नहीं थे। विचारों के स्तर पर इतने कट्टर थे कि कठमुल्ला कहना ही उचित होगा। पर ये बोलने में भी लोंगों की फूंक सरक जाती थी। कहने वाले कहते हैं कि नेताजी का काला चिट्ठा तो उनके जाने के बाद ही खुलेगा।उनके जीते जी तो असंभव ही समझो।यों कहावत भले ही कुछ हो आप नेताजी को देखकर या उनसे मिलकर कह सकते हैं-काले को काला कहो काला जाये रूठ।पर ये कहकर भी किसी को मरना है क्या।

मध्यप्रदेश पर्यटन दिवस

लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं और पर्यटन में विशेष रुचि रखते हैं।

समग्र पर्यटन का केंद्र है मध्यप्रदेश

चम्बल के भरकों से लेकर कटनी, उमरिया और जबलपुर से लगा शाहडार का जंगल भी रोमांचक यात्राओं का ठिकाना है। मेकल पर्वत पर सदानीरा माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ही नहीं, अपितु वहां का सघन वन भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मध्यप्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जहाँ सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, शिवपुरी, पन्ना और कई अन्य राष्ट्रीय उद्यान लोगों को वन्य जीवन को देखने का दुर्लभ, रोमांचपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। मध्यप्रदेश सफ़ेद बाघ 'मोहन' का ही घर नहीं है, अपितु यह रहस्य और कौतुहल बढ़ाने वाले बालक 'मोगली' का भी जन्मस्थान है। सर विलियम हेनरी स्लीमन ने एन एकाउंट ऑफ वाल्वस नरचरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेन्स शीर्षक से लिखे अपने एक दस्तावेज में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के जंगल (पेंच टाइगर रिजर्व) में मोगली का घर था। वाइल्डलाइफ पर्यटन मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के कारण मध्यप्रदेश के पास 'टाइगर स्टेट' के साथ ही द लेपर्ड स्टेट और घड़ियाल स्टेट का दर्जा भी है। बाघ देखने के लिए न केवल देशभर से बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से भी लोग मध्यप्रदेश में आते हैं। भिंड और मुरैना के समीप स्थित चम्बल सफारी तो घडियाल संरक्षण का बड़ा केंद्र बन गई है।

भारत का हृदय 'मध्यप्रदेश' अपनी नैसर्गिक सुन्दरता, आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्ध विरासत के चलते सदियों से यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। आत्मा को सुख देनेवाली प्रकृति, गौरव की अनुभूति करानेवाली धरोहर, रोमांच बढ़ानेवाला वन्य जीवन और विश्वास जगानेवाला अध्यात्म, इन सबका मेल मध्यप्रदेश को भारत के अन्य राज्यों से अलग पहचान देता है। इस प्रदेश में प्रत्येक श्रेणी के पर्यटकों के लिए कई चुम्बकीय स्थल हैं, जो उन्हें बरबस ही अपनी ओर खींच लेते हैं। यह प्रदेश उस बड़े हृदय के मेजबान की तरह है, जो किसी भी अतिथि को निराश नहीं करता है।

वैभव की इस भूमि पर पराक्रम की गाथाएं सुनाते और आसमान का मुख चूमते दुर्ग हैं। भारत का जिब्राल्टर 'ग्वालियर का किला', महेश्वर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर का राजमहल, मांडू का जहाज महल, दतिया में सतखंडा महल, रायसेन का दुर्ग, दुर्गावती का मदन महल, जलमग्न रहनेवाला रानी कमलापति का महल और गिन्नौरगढ़ सहित अनेक किले हैं, जो मध्यप्रदेश के स्थापत्य की विविधता का बखान करते हैं। देवों के चरण भी इस धरा पर पड़े हैं। उज्जैन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण पढ़े। चित्रकूट, जहाँ प्रभु श्रीराम माता सीता और भ्राता लखन सहित वनवास में रहे। ओंकारेश्वर, जहाँ आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने आचार्य गोविन्द भगवत्पाद से दीक्षा ली। मध्यप्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग- महाकाल और ओंकारेश्वर हैं। इसके साथ ही भगवान शिव ने कैलाश और काशी के बाद अमरकंटक को परिवार सहित रहने के लिए चुना है। एक ओर जहाँ द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण प्रतिवर्ष मुरैना में आकर ढ़ाई दिन रहते हैं तो वहीं ओरछा में राजा राम का शासन है। महारानी कुंवर गणेश के पीछे-पीछे श्रीराम अयोध्या से ओरछा तक चले आये थे। ओरछा राजाराम के मंदिर के लिए ही नहीं, अपितु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है।

मध्यप्रदेश अपने वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। सतपुड़ा के घने जंगल का तो अद्भुत वर्णन कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में आता ही है। चम्बल के भरकों से लेकर कटनी, उमरिया और जबलपुर से लगा शाहडार का जंगल भी रोमांचक यात्राओं का ठिकाना है। मेकल पर्वत पर सदानीरा माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ही नहीं, अपितु वहां का सघन वन भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मध्यप्रदेश भारत का इकलौता राज्य है जहाँ सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, शिवपुरी, पन्ना और कई अन्य राष्ट्रीय उद्यान लोगों को वन्य जीवन को देखने का दुर्लभ, रोमांचपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। मध्यप्रदेश सफ़ेद बाघ 'मोहन' का ही घर नहीं है, अपितु यह रहस्य और कौतुहल बढ़ानेवाले बालक 'मोगली' का भी जन्मस्थान है। सर विलियम हेनरी स्लीमन ने 'एन एकाउंट ऑफ वाल्वस नरचरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेन्स' शीर्षक से लिखे अपने एक दस्तावेज में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के जंगल (पेंच टाइगर रिजर्व) में मोगली का घर था। वाइल्डलाइफ पर्यटन मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के कारण मध्यप्रदेश के पास 'टाइगर स्टेट' के साथ ही 'द लेपर्ड स्टेट' और 'घड़ियाल स्टेट' का दर्जा भी है। बाघ देखने के लिए न केवल देशभर से बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से भी लोग मध्यप्रदेश में आते हैं। भिंड और मुरैना के समीप स्थित चम्बल सफारी तो घडियाल संरक्षण का बड़ा केंद्र बन गई है। कभी डाकुओं के लिए कुख्यात रहे चम्बल के बीहड़ अब डोल्फिन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में गंगा के बाद सबसे अधिक डोल्फिन चम्बल सफारी में पाए जाते हैं।

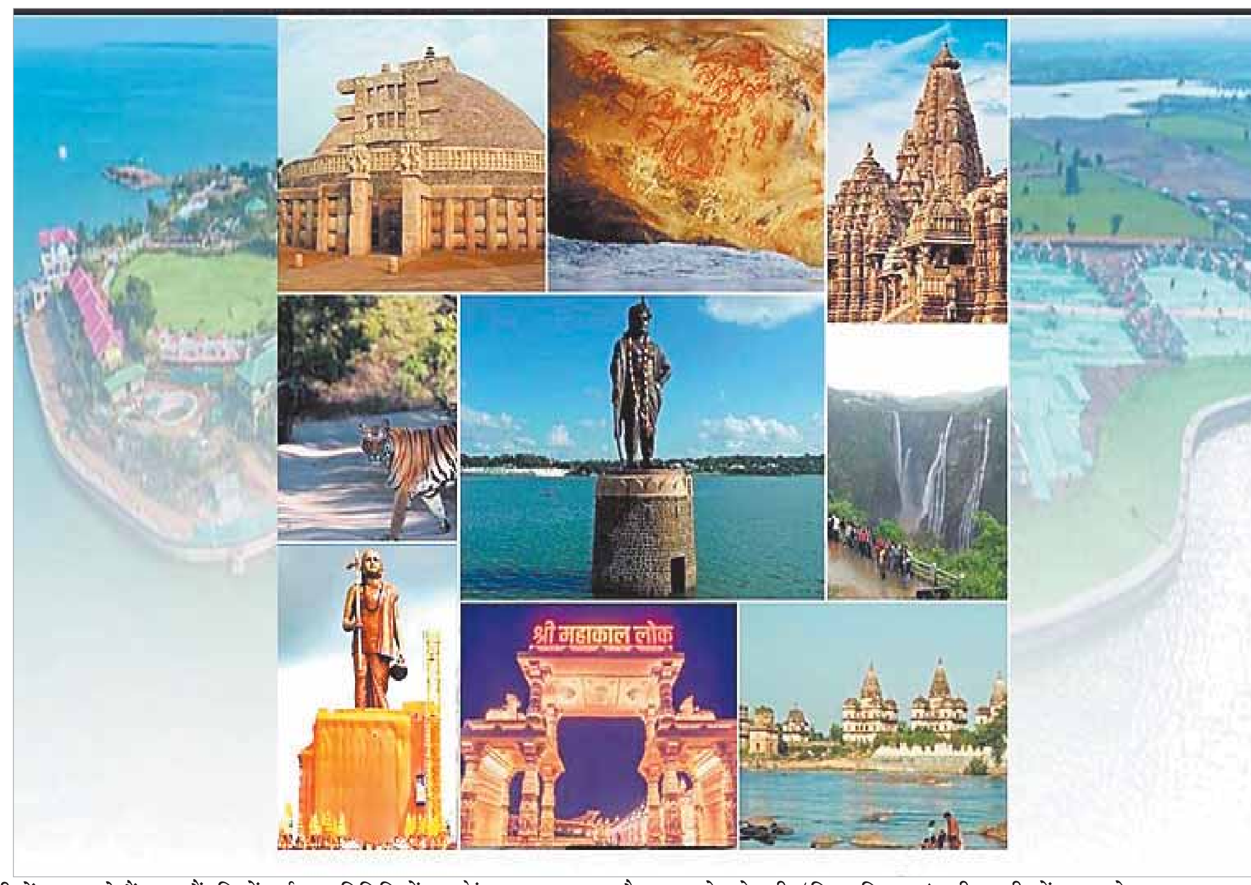

जनजातीय संस्कृति से साक्षात्कार करने का अवसर भी मध्यप्रदेशदेता है। मंडला, उमरिया, छिंदवाडा, बालाघाट, झाबुआ और अनूपपुर में कई स्थान हैं, जो पर्यटन के तौर पर विकसित किये गए हैं। कुछ समय के लिए दुनिया की भागम-भाग से दूर प्रकृति की गोद में सुख की अनुभूति करने केलिए तामिया और पातालकोट जैसे स्थान भी हैं, जो आम पर्यटकों से छिपे हुए हैं। वहीं, मढ़ई, तवा, परसिली, हनुमंतिया जैसे अनेक स्थल भी हैं, जिन्हें पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है। पर्यटकों द्वारा खोजे जा रहे नये पर्यटन स्थलों को भी व्यवस्थित करने में मध्यप्रदेश की सरकार अग्रणी है। इंदौर के समीप महू से पातालपानी-कालाकुंड तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन भी सीटी बजाकर उन पर्यटकों को बुलाती है, जो प्रकृति के नजारों में खोना चाहते हैं।

सब प्रकार के पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध मध्यप्रदेश के ऐसे अनेक स्थान हैं, जो अभी भी पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में यूनेस्को की 'विश्व विरासत' की सूची में मध्यप्रदेश केचार स्थल है- बुद्ध का सन्देश देते साँची के स्तूप, प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह भीमबेटिका, सौंदर्य के साक्षी खजुराहो के साथ त्यागमय संस्कृति का प्रतीक ओरछा। ये चारों ही स्थान विदेशी पर्यटकों को लुभाते हैं।

मध्यप्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है, जो पर्यटन की दृष्टि से मरुस्थल हो। ग्वालियर के आसपास ककनमठ, मितावली, पड़ावली, दतिया, सोनागिर, ओरछा, चंदेरी और शिवपुरी का एक ट्रेवल रूट बनता है। भोपाल के आसपास साँची, विदिशा, ग्यारसपुर, उदयगिरी की गुफाएं, भोजपुर, भीमबेटका, देलावाडी और रायसेन एक पर्यटन स्थल समूह बनता है। इंदौर को केंद्र मानकर उज्जैन, हनुमंतिया, ओंकारेश्वर, ब्रह्मपुर (बुरहानपुर), महेश्वर और मांडू का एक पर्यटन स्थल का समूह बनता है। वहीं, जबलपुर से भेड़ाघाट, बरगी, बांधवगढ़, अमरकंटक, कान्हा और पेंच जा सकते हैं। खजुराहो के साथ ओरछा, अजयगढ़, चित्रकूट, मुकुंदपुर वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मैहर और हीरों के साथ अपने जंगलों के लिए प्रसिद्ध पन्ना के पर्यटन स्थल घुमे जा सकते हैं। उधर, सतपुड़ा की रानी 'पचमढ़ी' के साथ मढ़ई, तवा, तामिया और पातालकोट का एक पर्यटन समूह बनता है। मध्यप्रदेश के पर्यटन, उसकी समृद्ध विरासत और गौरव का दर्शन करना है तो एक बार मध्यप्रदेश गान पढ़/सुन लेना चाहिए। वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार महेश श्रीवास्तव ने इस गीत में मध्यप्रदेश की एक खूबसूरत और गौरवपूर्ण तस्वीर उतार दी है।

मध्यप्रदेश घूमने का सबसे अच्छा समय वैसे तो मध्यप्रदेश राज्य का वर्ष के किसी भी समय दौरा किया जा सकता है। मध्य भारत में स्थित होने के कारण, मध्य प्रदेश की जलवायु आमतौर पर गर्मऔर शुष्क होती है। परन्तु अच्छा होगा कि अक्टूबर से मार्च के बीचमध्यप्रदेश घूमने की योजना बनायी जाए। इस दौरान यहाँ का तापमान अनुकूल होता है और बारिश के बाद कई पर्यटन स्थल अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ उपस्थित होते हैं। प्रदेश में सर्दियों का मौसम वन्यजीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक स्थलों, नदी घाटियों और प्राचीन मंदिरों में जाने के लिए एकदम सही है।

मुद्दा

– अनिल धीमान

लेखक खगोल विज्ञान के राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं।

बच्चों की आत्महत्या और हम

वो दौर अलग था जब नंबरों की दौड़ नहीं थी, उस दौर की शिक्षा से व्यक्ति संतुष्ट था। आज शिक्षा प्रतियोगिता की तरह हो चुकी है सब दौड़ रहे हैं जीतना चाहते हैं। जीतना सबको अच्छा लगता है। हारना कौन चाहता है क्योंकि हमारी कथाओं का अंत जीत पर ही ख़त्म होता है। लगभग हर माता पिता के सपनों को बच्चे बोझ की तरह ढो रहे हैं। बच्चे को क्या बनना है वो तय नहीं कर रहा है। माता पिता के समाज और आस पड़ोस का दबाव तय करता है। बच्चा विषय भी खुद तय नहीं करता माता पिता करते हैं। बच्चा आर्ट पढ़ना चाहता है, माता पिता कहते हैं, नहीं साइंस पढ़ो आदि आदि। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस से कम में बच्चो को कोई स्वीकारता नहीं। कहा जाता है यही भविष्य है।

कुछ दिन पहले अख़बार में भोपाल के अयोध्या बायपास में कटने वाले 8 हज़ार पेड़ों और परीक्षा में फेल होने के कारण आत्महत्या करने वाली छात्रा की खबरें सुर्खियां बनीं। लेकिन बड़ा समाज इन सबसे अछूता रहा। पेड़ का क्या वो तो काटते रहते हैं। बच्चों का क्या वो तो आत्महत्या करते रहते हैं। हमारी असंवेदी होती भावनाओं और आदतों के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये हमारी चिंता से परे हैं।

फेल होना गुनाह नहीं ना ही जिंदगी का अंतिम सत्य है। नंबरों की भागदौड़ में बच्चा दिनों दिन पीसता जा रहा है। 90 प्रतिशत से कम माता पिता को हज़्म नहीं होता। बच्चे के कम नंबर आए तो समाज और बाकी परिवार में सिर झुक जायेगा नाक काट जाएगी।

वो दौर अलग था जब नंबरों की दौड़ नहीं थी, उस दौर की शिक्षा से व्यक्ति संतुष्ट था। आज शिक्षा प्रतियोगिता की तरह हो चुकी है सब दौड़ रहे हैं जीतना चाहते हैं। जीतना सबको अच्छा लगता है। हारना कौन चाहता है क्योंकि हमारी कथाओं का अंत जीत पर ही ख़त्म होता है। लगभग हर माता पिता के सपनों को बच्चे बोझ की तरह ढो रहे हैं। बच्चे को क्या बनना है वो तय नहीं कर रहा है। माता पिता के समाज और आस पड़ोस का दबाव तय करता है। बच्चा विषय भी खुद तय नहीं करता माता पिता करते हैं। बच्चा आर्ट पढ़ना चाहता है, माता पिता कहते हैं, नहीं साइंस पढ़ो आदि आदि। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस से कम में बच्चो को कोई स्वीकारता नहीं। कहा जाता है यही भविष्य है।

कोई माता पिता नहीं चाहता की बच्चा आर्टिस्ट बने सिंगर बने या कोई भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, पुरातत्व, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन या फायर सर्विस इत्यादि में जाए। अब हम शायद अच्छेइंसान बनने की हिदायत देना भी भूल चुके हैं क्योंकि हम उन्हें जीतना सीखा रहे हैं हारना नहीं। हारना बहुत कुछ सिखाता है जिंदगी में। वैसे जीतना इतना मुश्किल नहीं है।

बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है, एक बार पूछ कर तो देखिए। संभव है राह निकल आए। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता क्योंकि उनके ख्वाब टूटने का दर उनको ऐसा करने से रोकता है और ये डर ही बच्चों को मानसिक परेशानी जैसी कई दिक्कतों से घेर लेता है और जब बच्चा सहन नहीं कर पाता किसी से बोल नहीं पाता तो उसका हल उसे आत्महत्या करने पर मज़बूर करता है।

मानसिक सेहत पर किताब

पूजा सिंह

समीक्षक

ज्यादा सोचने से कहीं अधिक जटिल होती है ओवरथिंकिंग

एक दशक से भी अधिक समय से मनोचिकित्सक के रूप में काम कर रहे डॉ. सत्यकांत चतुर्वेदी की यह पुस्तक 29 छोटे-छोटे अध्यायों में बंटी हुई है। ये अध्याय ओवरथिंकिंग के अलग-अलग प्रकार और पहलुओं से पाठकों को अवगत कराते हैं। उदाहरण के लिए कैसे एक समय के बाद ओवरथिंकिंग हमारे रिश्तों में तनाव की वजह बन जाती है, बच्चों में ओवरथिंकिंग के क्या प्रभाव होते हैं, ओवरथिंकिंग के लक्षण क्या होते हैं, ओवरथिंकिंग को लेकर समाज का सोच क्या है? लंबे समय तक ओवरथिंकिंग से कैसे बचें आदि। पुस्तक डीपथिंकिंग और ओवरथिंकिंग के अंतर से भी परिचय कराती है। इतना ही नहीं पुस्तक आधुनिक तकनीक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की भी विस्तार से पड़ताल करती है।

अगर आप ज़िंदगी में हर बात को जीने-मरने का प्रश्न बना देंगे तो यकीन मानिए आप एक नहीं कई-कई बार मरेंगे।

-डीन स्मिथ (ब्रिटिश फुटबॉलर)

ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। अक्सर हम अधिक सोचने को ही ओवरथिंकिंग मान बैठते हैं जबकि हकीकत में इसकी परिभाषा इतनी आसान नहीं है। यह अधिक सोचने से कहीं अधिक जटिल मनःस्थिति है। अपने जीवन में हम सभी कभी न कभी ओवरथिंकिंग से गुजरते हैं। तेज भागती आधुनिक जिंदगी में जब एक साथ-साथ कई-कई काम करने पड़ते हैं और अधूरे कामों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है तो ओवरथिंकिंग होना आम बात है। ओवरथिंकिंग के कारण धीरे-धीरे हमारी आदत कुछ ऐसी बन जाती है कि हम छोटी-छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा विचार करने लगते हैं। बीती बातों को याद करके दुखी होने लगते हैं। ऐसे में हम अनिवार्य रूप से अपने भविष्य को लेकर भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है- इसका नतीजा होता है निर्णय लेने में असमर्थता, नकारात्मक सोच और खुद पर संदेह करने की प्रवृत्ति।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रवृत्ति का अगला चरण मानसिक थकान और मानसिक समस्या के रूप में सामने आता है। परंतु यहां अच्छी बात यह है कि सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी द्वारा लिखी पुस्तक 'ओवरथिंकिंग से आज़ादी वन द बैटल ऑफ योर माइंड' न केवल ओवरथिंकिंग की समस्या को समझने में हमारी मदद करती है बल्कि आसानी से अपनाए जा सकने वाले उपायों की मदद से ओवरथिंकिंग से निजात पाने का भरोसा भी दिलाती है।

एक दशक से भी अधिक समय से मनोचिकित्सक के रूप में काम कर रहे डॉ. सत्यकांत चतुर्वेदी की यह पुस्तक 29 छोटे-छोटे अध्यायों में बंटी हुई है। ये अध्याय ओवरथिंकिंग के अलग-अलग प्रकार और पहलुओं से पाठकों को अवगत कराते हैं। उदाहरण के लिए कैसे एक समय के बाद ओवरथिंकिंग हमारे रिश्तों में तनाव की वजह बन जाती है, बच्चों में ओवरथिंकिंग के क्या प्रभाव होते हैं, ओवरथिंकिंग के लक्षण क्या होते हैं, ओवरथिंकिंग को लेकर समाज का सोच क्या है? लंबे समय तक ओवरथिंकिंग से कैसे बचें आदि। पुस्तक डीपथिंकिंग और ओवरथिंकिंग के अंतर से भी परिचय कराती है।

इतना ही नहीं पुस्तक आधुनिक तकनीक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की भी विस्तार से पड़ताल करती है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, इंटरनेट पर अधिक जानकारी जुटाने से संबंधित भ्रम किस तरह हमारी दिमागी सेहत को प्रभावित करते हैं यह भी पुस्तक में बताया गया है। पुस्तक के हर अध्याय में कहानियों के जरिये ओवरथिंकिंग को स्पष्ट करने के साथ ही पांच-पांच सीख भी बिंदुवार प्रस्तुत की गई हैं जिनके माध्यम से उस अध्याय का सार ग्रहण किया जा सकता है।

पुस्तक का पहला ही अध्याय पाठकों को न केवल अपने साथ जोड़ता है बल्कि ओवरथिंकिंग से जूझ रहे लोगों को संबल भी देता है। 'प्रियंका का आंसू से मुस्कान का सफर' नामक इस अध्याय में प्रियंका नामक एक हाउसवाइफ अपनी जुबानी अपनी कहानी कहती है। प्रियंका की कहानी दरअसल देश के उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी समस्या को पहचानते तो हैं लेकिन कई कारणों से उसका निदान नहीं ले पाते। कभी अपने ही मन की दुविधा आड़े आ जाती है तो कभी आसपास के लोगों और समाज की मानसिक समस्याओं को लेकर लापरवाह सोच उनकी राह रोक लेती है। प्रियंका की कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। वह यह कि किसी भी मानसिक समस्या की स्थिति में चिकित्सकीय सलाह और इलाज अवश्य लें और हालात में सुधार होने पर भी स्वयं, अपने परिवार या दोस्तों के कहने पर दवाएं बंद न करें। मानसिक स्वास्थ्य की दवाएं हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन से जुड़ी होती हैं जो अत्यधिक नाजुक होता है, ऐसे में चिकित्सक के अलावा किसी अन्य पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए।

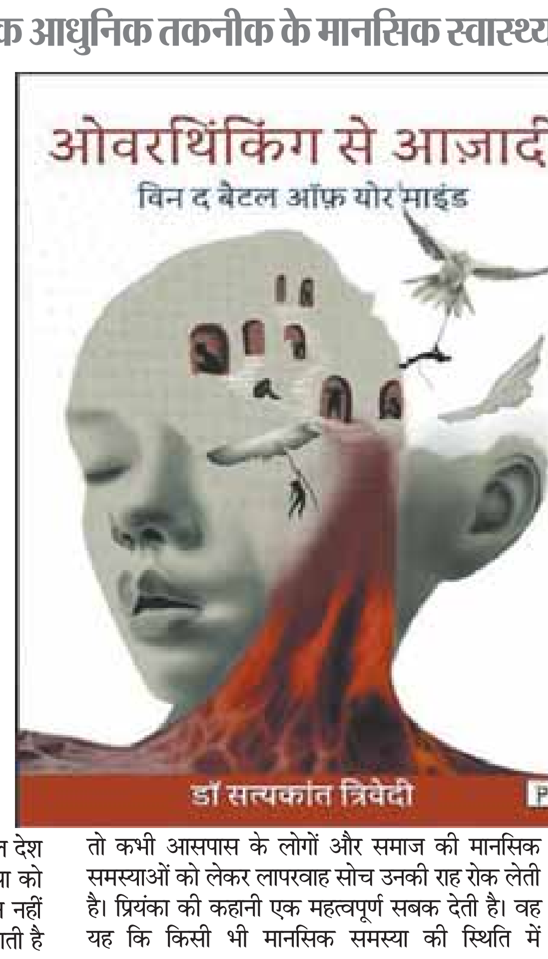

पुस्तक के अन्य अध्याय भी हमारे आसपास के मध्यवर्गीय जीवन के चरित्रों की दुविधाओं, उनके जीवन की घटनाओं के माध्यम से ओवरथिंकिंग के अलग-अलग प्रकार को न केवल समझाने वाली शैली में पाठकों के सामने रखते हैं बल्कि ये छोटी कहानियां पाठकों की मदद भी करती हैं ताकि अगर उनमें ऐसे कोई लक्षण हैं तो वे इन्हें चिन्हित करके जरूरी कदम उठा सकें।

ओवरथिंकिंग को लेकर किसी को भी लग सकता है कि सोचते तो सभी हैं कुछ लोग थोड़ा अधिक सोचते हैं इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं है।

डेनमार्क की मशहूर मनोविज्ञानी और मेटाकॉग्निटिव स्पेशलिस्ट पिया कल्लेसेन अपने एक आलेख में लिखती हैं, ओवरथिंकिंग एक दुष्चक्र रच देती है। लगातार अधिक सोचने से आपकी नींद गायब हो सकती है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ सकती है और थकान महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं यह आगे बढ़कर एंग्जाइटी या डिप्रेसन की वजह बन सकता है।

डॉ. त्रिवेदी की किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग के भी कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार की ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए एक ही तरीका नहीं अपनाया जा सकता है। अलग-अलग प्रकार की ओवरथिंकिंग के लिए अलग-अलग तरह की योजना तैयार करनी होती है। ओवरथिंकिंग एक आदत है जो हम अपने आप में डाल लेते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रयास करके उसे बदला जा सकता है।

आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता।
आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता।
कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर
आदमी मर जाता है।

मशहूर कवि-कथाकार उदय प्रकाश की कविता की ये पंक्तियां दरअसल यही तो कहती हैं कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। सोचना और हर मुद्दे पर अपना स्वतंत्र विचार रखना मनुष्य होने की अनिवार्य शर्त है। परंतु क्या होता है जब हम बहुत अधिक सोचना शुरू कर देते हैं? सोचने पर किसी का वश नहीं। एक चिकित्सक, एक कारोबारी, एक गृहणी, एक छात्र, एक किसान, इन सभी के सिर पर सोच की एक अदृश्य गठरी होती है। यह गठरी किसी को दिखती नहीं लेकिन उसे हर व्यक्ति ढोता है।

पुरानी कहावत है कि समस्या को पहचानना और उसे स्वीकार करना आधी समस्या को हल कर देता है। ओवरथिंकिंग पर भी यह बात लागू होती है। अपनी समस्या को पहचान कर उससे निपटने की नीतियां बनाई जा सकती हैं। डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी की यह महत्वपूर्ण पुस्तक लाखों लोगों को ओवरथिंकिंग से निजात पाने में मदद कर सकती है।

पुस्तक- ओवरथिंकिंग से आज़ादी
लेखक- डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी
प्रकाशक- प्लसप्रमेश
मूल्य- 300 रुपये

जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब प्रकट होते हैं भगवान: स्वामी चंद्रशेखरानंद

श्री हनुमान माता मंदिर पुलिस लाइन, टैगोर वार्ड में चल रही महाशिव पुराण कथा

बैतूल। पृथ्वी पर जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब भगवान सगुण साकार रूप लेकर प्रकट होते हैं। भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए आते हैं। उक्त प्रवचन श्री हनुमान माता मंदिर पुलिस लाइन, टैगोर वार्ड बैतूल परिसर में चल रही महाशिवपुराण कथा में स्वामी चंद्रशेखरानंद महाराज, श्रीविद्या साधनापीठ शिवपुर ने कही। शिवलिंग की पूजा का बताया महत्व स्वामी जी ने कहा कि भगवान ही सृष्टि बनाते हैं, भगवान रुद्र ही सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले है। सतयुग में रत्न की शिवलिंग की उपासना करने से शिवकलोक प्राप्त होता था। त्रेता में द्वापर में पारद और कुलयुग में पार्थिवलिंग का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

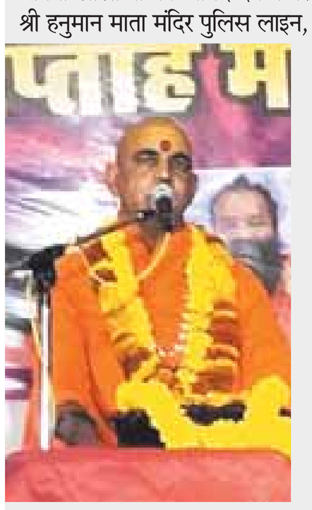

चार अंगुल का बनाना चाहिए शिवलिंग- उन्होंने कहा कि शिवलिंग पार्थिव को अखण्ड बनाना चाहिए। एक मिट्टी से ही शिवलिंग बनाना चाहिए। चार अंगुल पार्थिव लिंग बनाना चाहिए। बिल्वपत्र के बिना पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन के तीन अंग है। रुद्राक्ष, भस्म, जप जो इनको धारण करता है और पूजन करता है वह चलता फिरता शिव रुप ही माना जाता है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग कर निर्माण और अभिषेक किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पं. अनुराग मिश्रा ने सभी धर्मप्रेमी जनता से कथा श्रवण करने की अपील की है।

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नि की हत्या

- आरोपी पति को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

बैतूल। पत्नि की हत्या करने के मामले में पति के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज तपेश कुमार दुबे ने आरोपी छन्नू सेलुकर (42) को आजीवन कारावास के साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना 3 जुलाई 2023 को मोरडोंगरी गांव में हुई। आरोपी छन्नू ने अपनी पत्नि रूपा से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पत्नि के मना करने पर उसने लाठियों से उसकी पिटाई कर दी। वह घर के समाने सडक़ पर उसे लाठियों से पीट रहा था। इस दौरान गांव का कोटवार बैनाबाई ने छन्नू को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और उल्टा उन्हें भी धमकाया। पिटाई के बाद जब रूपा बेहोश हो गई, तो छन्नू उसे घर के अंदर लेकर चला गया। दोपहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जब घर में जाकर देखा तो रूपा की मौत हो चुकी थी। पत्नि की मौत के बाद छन्नू मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मृतिका का शव बरामद कर उसका पीएम करवाया और मायका पक्ष को सौंप दिया। पुलिस ने घटना के दो दिन बाद 5 जुलाई को फरार आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कोर्ट में डॉ. अशोक नरवरे ने बताया कि मारपीट के कारण कोमा में जाने से रूपा की मृत्यु हुई। वकील जगदीश परते ने इस मामले में पैरवी की।

माचना डैम और ताप्ती बैराज के पानी को मिलाकर वर्तमान में हो रही थी सप्लाई, अब बनी नई व्यवस्था

माचना का जलस्तर गिरने और ताप्ती बैराज की मोटर खराब होने से अब दो दिन के अंतराल पर भी नहीं मिल रहा पानी

संजय द्विवेदी, बैतूल। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, जलस्त्रोतों में पानी का लेवल भी कम होता जा रहा है। जिसका परिणाम यह है कि अब शहर में एक दिन के अंतराल के बजाए दो दिन के अंतराल पर भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल माचना नदी का जलस्तर गिरने के कारण शहर में जलसंकट के हालत बनने लगे हैं। नगरपालिका ने माचना डैम का पानी खत्म होने के चलते शहर में दो दिन के अंतराल से पेयजल सप्लाई करने का निर्णय लिया। परंतु अब हालात यह है कि शहर के 33 वार्डो में दो दिन के अंतराल से भी पेयजल की सप्लाई नही हो पा रही है। जिससे शहरवासियों को बारिश आने तक जलसंकट के हालातों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में नगरपालिका द्वारा दो दिन के अंतराल से ही वार्डो में पेयजल की सप्लाई कर रही है, इसमें भी कई वार्डों में पर्याप्त नल नहीं आने के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हैं। ऐसे में दो दिन के अंतराल से पेयजल सप्लाई से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी में पानी की खपत वैसे भी दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाना मुश्किल हो रहा हैं।

माचना-ताप्ती के पानी से कर रहे जल सप्लाई -नगरपालिका पहले माचना डैम और ताप्ती बैराज से आधा-आधा पानी लेकर शहर में एक दिन के अंतराल से पेयजल की सप्लाई कर रही थी, जब तक माचना डैम में पानी का स्तर ठीकठाक था

तब तक पेयजल सप्लाई में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन माचना डैम का पानी खत्म होने के कारण नपा को दो दिन के अंतराल में पेयजल सप्लाई शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा। फिलहाल शहरवासियों को बारिश होने तक जल संकट से जूझना पड़ेगा।

ताप्ती बैराज पर बढ़ा वॉटर सप्लाई का दारोमदार -माचना डैम में पानी खत्म होने के कारण अब रॉ वॉटर की सप्लाई का दारोमदार ताप्ती बैराज पर निर्भर हो गया है। ताप्ती के इंटकवेल में तीन मोटरें लगी हैं जो पानी की सप्लाई बैतूल तक करती है। चूंकि इनमें से एक मोटर के खराब होने पर सिर्फ एक मोटर ही वर्तमान में चालू रह पा रही है इसलिए समस्या बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक गर्मी के मौसम में मोटरों को लगातार चलाया भी नहीं जा सकता, इसलिए दो में से एक मोटर को ही, एक समय में सिर्फ एक मोटर ही चालू रह पाती है, इससे भी रॉ वाटर की सप्लाई में ज्यादा समय लग रहा है। ऐसे में एक दिन में सभी वार्डों की टंकियों को भर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण पेयजल सप्लाई में दिक्कत जा रही है।

नपाध्यक्ष और सीएमओ ने किया प्लांट का निरीक्षण -शहर में जलसंकट के हालत निर्मित न हो इसे देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर और सीएमओ सतीश मटसेनिया, नपा सब इंजिनियर ने ताप्ती बैराज एवं फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट का संचालन और मशीनों के रखरखाव की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमति बारस्कर ने ठेकेदार को मोटर खराब होने पर जमकर लताड़ा, उन्होंने मोटर का मेंटेनेस करने वाले ठेकेदार को मोटर के स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा रखने की हिदायत दी, अन्यथा कार्यवाही की चेतावनी भी दी। इसके बााद माचना डैम का निरीक्षण कर डैम और नदी में पानी के स्तर को देखा। जिसके बाद पेयजल सप्लाई के लिए उचित निणय लिये। गर्मी के दिनों में आम दिनों की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में दो तीन दिन के अंतराल में पानी मिलने से लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

इनका कहना है -

माचना डैम में पानी खत्म हो गया है। माचना डैम और ताप्ती बैराज का पानी लेकर अभी तक शहर में पेयजल सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब माचना डैम में पानी खत्म होने से समस्या आ रही है। ताप्ती बैराज की मोटर को भोपाल से इंजिनियर बुलवाकर सुधरवाया जा रहा है। कल तक ताप्ती की दूसरी मोटर भी चालू हो जाएगी, जिसके बाद शहर में पेयजल सप्लाई सुचारू हो जाएगी।

-- सतीश मटसेनिया, सीएमओ नगरपालिका बैतूल

पेयजल संकट के विरोध में आज नगर पालिका के सामने धरना देंगे कांग्रेस के संगठन

बैतूल। भीषण गर्मी में शहर पेयजल संकट से बुरी तरह जूझ रहा है और नगर पालिका की लापरवाही के खिलाफ अब कांग्रेस मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान ने बताया कि आज 24 मई को कांग्रेस के विभिन्न संगठन नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। श्री दीवान ने बताया कि गर्मी की शुरुआत होते ही उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को जलसंकट की आशंका को लेकर कई बार चेताया था, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा कर दिया गया। समय रहते वैकल्पिक जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई, जिसका नतीजा आज यह है कि शहर की अधिकांश कॉलोनियों, मोहल्लों और वार्डों में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। श्री दीवान ने बताया कि कांग्रेस के सभी प्रमुख संगठन इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदर्शन के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन को चेताया जाएगा कि अगर तत्काल पेयजल संकट पर कार्यवाही नहीं हुई, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

कृष्णा नगर बडोरा में रास्ते पर हो रहा अतिक्रमण

रहवासी परेशान, कलेक्टर को ज्ञापन देकर की शिकायत

बैतूल। बैतूलबाजार रोड स्थित कृष्णा नगर बडोरा के रहवासियों ने कलेक्टर को शिकायत कर महाराजा मोटर्स के पास हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। रहवासियों का कहना है कि वे सभी बैतूल बाजार रोड पर स्थित कृष्णा नगर बडोरा, महाराजा मोटर्स के पीछे निवास करते हैं। उनकी कॉलोनी का रास्ता मुख्य मार्ग बैतूल-नागपुर रोड से अंदर की ओर आता है, लेकिन जैसे ही मुख्य मार्ग से अंदर प्रवेश करते हैं, वहां अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे रास्ता सकरा हो गया है और कॉलोनी के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी तहसीलदार को भी एक लिखित आवेदन 21 मार्च 2025 को सौंपा था, परंतु अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद रहवासियों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। रहवासियों का आरोप है कि शिकायत के बाद तहसीलदार ने यह कहते हुए शिकायत बंद करवा दी कि अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा और जो निर्माण हो रहा है उसे तोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक अवैध अतिक्रमण पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तहसीलदार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से रहवासियों में जबरदस्त रोष है।

रहवासियों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने अतिक्रमण कर रहे व्यक्ति का पक्ष सुना और उसके प्लॉट की नाप जोख करवाकर उसे निर्माण कार्य की अनुमति दे दी, जबकि इस संबंध में हमें कोई सूचना तक नहीं दी गई और न ही सीमांकन किया गया। रहवासियों का कहना है कि जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, वहां सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद क्रमांक 22ए/2010 में आदेश पारित कर रास्ता मान्य किया गया है। इसके अलावा जिन दस्तावेजों से अनिरुद्ध घनश्याम सोनी ने प्लॉट खरीदा है, उनमें भी रास्ते का स्पष्ट उल्लेख है। यह प्लॉट श्री अनिरुद्ध ने श्री चौरे और श्री वीरेंद्र करणे से खरीदा था, जिनके द्वारा भी रास्ता छोड़ा गया था। रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ते से अतिक्रमण हटवाया जाए, ताकि कॉलोनी वासियों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश और रजिस्ट्री के दस्तावेजों की अनदेखी कर तहसीलदार द्वारा पक्षपातपूर्ण एकतरफा कार्रवाही कर जबरदस्ती निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है। रहवासियों ने कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। शिकायत करने वालों में पूर्व विधायक शिवप्रसाद राठौर, रामकुमार किरार, एनआर अडलक, जगदीश बारपेटे, लोकेश पटैया, राम बारस्कर, एनएल हारोडे, राजकुमार राठौर, पांडुरंग चिल्हाटे, सतीश पवार, दयानंद लिलहोरे, द्वारका प्रसाद सोनी, एसडी बाथरी, राजेंद्र पवार, एनके धाकड़, दिनेश सूर्यवंशी, दिनेश हारोडे, एचएन साहू, शिवचरण कापसे, महेश सिसोदिया, पंकज, सतीश, राजेश साहू, कैलाश पंडाग्रे, बीआर पंडाग्रे सहित बड़ी संख्या में वार्ड के रहवासी शामिल थे।

कोतवाली पुलिस ने गौवंश को कत्लखाना ले जाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

जप्तशुदा गौवंश को त्रिवेणी गौशाला झगड़िया के किया सुपुर्द

बैतूल। जिले के कोतवाली और भैंसदेही पुलिस ने गौवंश को कत्लखाना ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जप्त शुदा गौवंश को गौशाला के सुपुर्द किया गया और आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लडक़ा 3 मवेशी गौवंश को क्रुरूरतापूर्वक भूखे प्यासे खदेड़ता हुआ मारपीट करते कत्लखाने ले जा रहा है। पुलिस को ग्राम माथनी के अनिल पारधी के खेत के पास एक लडका 3 मवेशी गौवंश के साथ दिखा, जिसे रोका गया। लडके को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम पर्वत पिता कैलाश धुर्वे 25 साल निवासी वार्ड नं. 15 पीर गली, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम का होना बताया तथा अवैध रूप से 03 मवेशी गौवंश को क्रुरूरतापूर्वक भूखे प्यासे खदेडता हुआ मारपीट करते हुये कत्लखाने ले जाना बताया। पुलिस ने धारा 4,6,9 मध्य प्रदेश गोवंश बध प्रतिषेध अधिनियम , 11(1) (घ) पशु क्रुरूरता निवारण अधिनियम का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। गिरप्तार शुदा आरोपियो को न्यायालय पेश किया गया। इस कार्रवाही में थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया, उनि जगदीश प्रसाद ठाकुर, प्र आर ब्रिजेश रघुवंशी, प्र.आर. दिनेश निमोदा, आर. जतिराम की सराहनीय भूमिका रही।

होमगार्ड कार्यालय बैतूल में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित

बैतूल। जिले के होमगार्ड कार्यालय में एक दिवसीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन जिला सेनानी इंदल उपनारे के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में हवलदार अनुदेशक बलिराम सरयाम, होमगार्ड तथा एसडीईआरएफ के जवानों की उपस्थिति में कुल 47 सिविल डिफेंस वालंटियर्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान वालंटियर्स को आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा की भूमिका, प्रकार तथा इसकी विभिन्न सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को यह बताया गया कि किस प्रकार आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा बल प्रभावी भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान हवाई हमले के समय बजने वाले विभिन्न प्रकार के सायरनों की पहचान और उनका महत्व, बिजली एवं रोशनी के पूर्ण बंदी के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इसके अलावा आपातकाल में भीड़ को नियंत्रित करने की रणनीतियों का अभ्यास करवाया गया। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में खोज एवं बचाव कार्यों की प्रक्रिया का मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार देना, पट्टी बांधना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाने की तकनीकों का अभ्यास करवाया गया।

नगर पालिका भवन एवं गार्डन निर्माण की गति धीमी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल

नगर पालिका उपयंत्री ने जारी के नोटिस

बैतूल /मुलताई। मुलताई नगर पालिका द्वारा नगर में करोड रुपए के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, किंतु हमेशा की तरह इस बार भी कार्य की गति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिसको लेकर उपयंत्री सुभाष शर्मा ने नगर पालिका परिसर में बन रहे नगर पालिका भवन एवं सूर्यनारायण सरोवर के समक्ष बन रहे बगीचे के ठेकेदार को निर्माण कार्य की गति एवं गुणवत्ता को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर पालिका भवन निर्माण एवं सूर्य नारायण सरोवर के समक्ष बगीचा निर्माण दोनों ही कार्य पवित्र नगरी के लिए महत्वपूर्ण कार्य माने जा रहे हैं, किंतु इनके साथ ही इन कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आरंभ से ही सवाल उठने लगे थे। निर्माण प्रारंभ होते ही यह आशंका जन्म लेने लगी थी कि क्या यह निर्माण कार्य समय के साथ टिक पाएंगे या अल्प समय में ही अन्य कार्यों की भांति धराशाई हो जाएंगे। नगर पालिका उपयंत्री ने ठेकेदारों को नोटिस जारी कर यह उम्मीद तो बधाई है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नगर पालिका ध्यान दे रही है किंतु यह देखना होगा कि क्या नोटिस के बाद ठेकेदार के कार्य प्रणाली में सुधार हो पता है अथवा नहीं।

नगर पालिका भवन निर्माण की धीमी है गति - मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चतुर्थ चरण के तहत नगर पालिका परिसर में बना रहे नगर पालिका भवन जिसकी लागत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, इसका ठेका तनुष्का कंस्ट्रक्शन भोपाल को दिया गया है। नगर पालिका के इंजीनियर ने उक्त ठेकेदार को नोटिस जारी कर कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है वही कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उक्त भवन की फ्लिंत का कार्य वर्षा काल से पूर्व ऊपर आ जाना था, किंतु जिस प्रकार की गति है वह संतोषजनक नहीं है। बताया जा रहा है कि उक्त ठेकेदार द्वारा मुलताई नगर में पूर्व में भी सडक़ों का निर्माण किया गया था जिन सडक़ों ने अल्प समय में ही दम तोड़ दिया था जबकि सभी सडक़ गारंटी अवधि में थी।

5 जून तक पूर्ण होना है गार्डन निर्माण कार्य - अमृत 2.0 योजना के तहत 41 लाख की लागत से सूर्यनारायण सरोवर के समक्ष हो रहे गार्डन निर्माण का कार्य 5 जून तक पूर्ण होना है, किंतु वर्तमान कार्य की गति को देखकर समय सीमा में कार्य का पूर्ण होना संभव नहीं लगता। जिसके चलते उपयंत्री द्वारा केयरवेल कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर कार्य की गति और कार्य की गुणवत्ता को लेकर जवाब मांगा है।

इनका कहना है -

नगर में चल रहा निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो और गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए ठेकेदारों को निर्माण कार्य में गति लाने और कार्य की गुणवत्ता को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं।

- सुभाष शर्मा, उपयंत्री नगर पालिका मुलताई

22 मई को चालू हुआ कुंडी टोल प्लाजा, 23 मई को कांग्रेस पार्टी के विरोध पर घंटे भर रहा बंद

बैतूल। शाहपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एनएच 46 पर बना नवनिर्मित कुंडी टोल प्लाजा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के धरना प्रदर्शन पर लगभग घंटे भर के लिए बंद रहा। दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के धरना प्रदर्शन पर टोल बंद किया गया। धरने का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत वागद्रे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा ने किया। धरने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिकों एवं ग्रामीणों ने हाईवे पर एकत्रित होकर नेशनल हाईवे पर टोल वसूली के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हाईवे को बंद कर दिया। जिससे टोल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस अवसर पर एनएचएआई का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों ने एनएचएआई के अधिकारियों, टोल मैनेजर और एसडीओपी मयंक तिवारी से बातचीत की। जाम लगने के कारण अधिकारियों ने टोल वसूली को कुछ देर के लिए बंद करवाया। इस दौरान वाहनों को किसी तरह निकाला जा सका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत प्रभाव से टोल वसूली को समाप्त करने की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में हाईवे का निर्माण कार्य अधूरा है, जिसके कारण बरेठा घाट

पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि जगह-जगह गड्ढे हैं, रोड असमतल है, और बाईपास पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद टोल प्लाजा प्रारंभ कर दिया गया ,जो जनता के साथ अन्याय है इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत वागद्रे ने कहा कि टोल शुरू करने के पहले मानक गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। भौंरा के आगे रोड कम्पलीट नहीं है डिवाइडर कंप्लीट नहीं है। जब तक बरेठा घाट और भौंरा एवं इटारसी के बीच का फोरलेन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक यहां टैक्स की वसूली नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फोरलेन जितना भी अब तक निर्मित हुआ है वह भी रोड नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके एलाइनमेंट और गुणवत्ता की किसी एक्सपर्ट एजेंसी से यदि जांच करा ली जाए तो वह इसे टेक्निकली फेल घोषित कर देगी।

इनका कहना है -

टोल को बंद करने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। यह भारत सरकार का उपक्रम है, उसके अधीन ही रहता है। आज हुए विरोध प्रदर्शन की सूचना एनएचएआई के अधिकारियों एवं कलेक्टर को दे दी गई। यदि टोल ठेकेदार के कर्मचारी नागरिकों से नियमों के विरूद्ध वसूली कर रहे हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

- अभिजीत सिंह, एसडीएम, शाहपुर

ठेकेदार को लाभ पहुंचाने अधूरी सड़क पर शुरू हुआ टोल

जिला अभिभाषक संघ ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन

बैतूल। बैतूल जिले के अधिवक्ताओं ने अधूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर टोल वसूली शुरू किए जाने का विरोध किया है। जिला अभिभाषक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर कुंडी टोल को तत्काल बंद करने की मांग की। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि बैतूल के मिलानपुर टोल से पाढर और बरेठा होते हुए भोपाल की ओर जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन है, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद शाहपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कुंडी के पास बनाए गए टोल प्लाजा को 22 मई से चालू कर दिया गया है। संजय कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि बैतूल से कुंडी टोल तक और कुंडी टोल से बागदेव, इटारसी की दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कहीं सडक़ कच्ची है, तो कहीं पुल-पुलियों का निर्माण अधूरा है। बावजूद इसके एनएच विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस अधूरी सडक़ पर टोल शुरू करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बन जाता, तब तक टोल वसूली जनता के साथ अन्याय है। अधूरी सडक़ पर टोल वसूली करना नियमों के भी खिलाफ है। जिला अभिभाषक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि कुंडी टोल को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और एनएच विभाग के अधिकारियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सप्रे संग्रहालय की डिजिटाइजेशन परियोजना से राज्यपाल संतुष्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना– 20,01,994 पृष्ठों का डिजिटाइजेशन, 10 के.वी. के सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना और सप्रे संग्रहालय में संगृहीत राष्ट्रीय बौद्धिक धरोहर की अद्यतन संदर्भिका की वेबसाइट के निर्माण– के पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त किया है। राज्यपाल ने सप्रे संग्रहालय को शुभकामनाएं दीं। 23 अक्टूबर, 2023 क राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इस परियोजना का शुभारंभ किया था। सामाजिक सेवा बैंकिंग के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने इस परियोजना के लिए सीएसआर निधि से धनराशि उपलब्ध कराई है।

यद्यपि सप्रे संग्रहालय में 5 करोड़ पृष्ठों से अधिक संदर्भ सामग्री संगृहीत है, लेकिन प्रथम चरण में 27 लाख उन पत्र-पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों को डिजिटाइज़ किया गया है जो जर्जर अवस्था में हैं,अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से सात लाख पृष्ठों का डिजिटाइजेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और मध्यप्रदेश जनसंपर्क के सहयोग से हुआ है।

इस पूरी आयोजना के स्वप्नदृष्टा सप्रे संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर ने 23 मई को राज्यपाल से भेंटकर परियोजना की सफल परिणति से अवगत कराया। डिजिटाइज्ड दस्तावेजों की संदर्भिका भी राज्यपाल को भेंट की। इस अवसर पर संग्रहालय के निदेशक अरविन्द श्रीधर भी उपस्थित रहे।

स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करें : उप मुख्यमंत्री

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सुबह रीवा के नगर वन का भ्रमण किया। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को नगर वन की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने नगर वन में सुबह की सैर कर रहे आमजनों से संवाद करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हम यदि पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावारण में सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।

'ऑपरेशन सिन्दूर' एक यात्रा है ,पड़ाव नहीं

● ऑपरेशन सिन्दूर सैन्य, सामरिक और राजनयिक दृष्टिकोण से भारत की निर्णायक विजय: एयर कोमोडोर मृगेंद्र सिंह ,रक्षा मामलों के विशेषज्ञ ● ऑपरेशन सिंदूर सैन्य सफलता भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और वैश्विक रणनीतिक समझ का भी प्रमाण है: प्रो. राका आर्य,विदेश मामलों की विशेषज्ञ

भोपाल। सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और समृद्ध सैन्य शक्ति से भारत आज न केवल सामरिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक प्रभावशाली और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभरा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय वायु सेना, थल सेना, नौसेना और राजनयिक तंत्र की समन्वित रणनीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब हर चुनौती का मुंहतोड़ उत्तर देने में सक्षम है। ये विचार सुरक्षा विशेषज्ञों, विचारकों और बुद्धजीवियों ने प्रज्ञा प्रवाह द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर : सैन्य, सामरिक और राजनयिक उपलब्धियाँ विषय पर आयोजित विशेष संवाद में व्यक्त किए।

एयर कोमोडोर मृगेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भारतीय वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार आधुनिक तकनीकों, सटीक योजना और असाधारण युद्ध कौशल के माध्यम से वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सैन्य सफलता नहीं, बल्कि भारत की वायु प्रतिरक्षा और आक्रमण क्षमता की विश्व को दिखाई गई एक शानदार झलक थी। भारत अब हर परिस्थिति में त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक क्षमता, तकनीकी श्रेष्ठता और अद्वितीय समन्वय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने लक्ष्यभेदी हमलों के माध्यम से आतंक के ढांचों और उनके सैन्य समर्थन को सटीकता और संयम के साथ निष्क्रिय किया – जिससे न केवल हमारी सैन्य शक्ति, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी नैतिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। यह एक त्रि-सेवा अभियान था, जिसमें राफेल, ब्रह्मोस, शौर्य मिसाइलों से लेकर अंतरिक्ष आधारित निगरानी तंत्र तक का अद्वितीय समन्वय देखा गया। हमारी एयर डिफेंस प्रणाली – एस-400, बराक-8 और आकाश – ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाया।

ब्रिगेडियर संजोय घोष ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के आतंकी प्रयास या सीमा पर अतिक्रमण को भारत कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है जो किसी भी स्थिति से निर्णायक, ठोस और समयबद्ध रूप से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सेना की यह तत्परता और साहस हमारी संप्रभुता की सुरक्षा की गारंटी है।इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में भी हमने पाकिस्तानी और चीनी तकनीकों को पछाड़ते हुए स्पष्ट बढ़त बनाई। बिना किसी पूर्ण सैन्य लामबंदी के, हमने रणनीतिक तैनाती और नियंत्रित प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने उद्देश्य प्राप्त किए। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता – भारत निर्णायक और प्रबल रूप से नेतृत्व करता है।

प्रो. डॉ. राका आर्य (प्रो. एनएलआईयू) ने कहा कि -ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, यह भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और वैश्विक रणनीतिक समझ का भी प्रमाण है। हमने अमेरिका, फ्रांस, रूस और खाड़ी देशों जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों को समय रहते यह स्पष्ट किया कि हमारी कार्यवाही आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार है – न कि युद्ध की शुरुआत। भारतीय कूटनीति ने वैश्विक जनमत को पूर्ववत संभालते हुए, न केवल विरोध की संभावनाएं न्यूनतम कीं, बल्कि कई देशों का समर्थन या तटस्थता भी सुनिश्चित की। भारत सैन्य दृष्टि से पूरी तरह तैयार था, लेकिन हमने यह भी दर्शाया कि रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के बाद हम संघर्षविराम के लिए खुले हैं । यह संयम और संकल्प की वह नीति है, जो आज भारत को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में ला रही है।

इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, जिज्ञासु युवा, शिक्षाविद एवं नीति-विश्लेषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संवाद सत्र के दौरान उपस्थित प्रबुद्धजनों ने विषय विशेषज्ञों से प्रश्न किये। सभी वक्ताओं ने भारत की सुरक्षा नीति, सेना की प्रतिबद्धता और देश के हितों की रक्षा में सक्रिय भूमिका की सराहना की।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने चिरहुला नाथ मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद, नवविवाहितों को दी शुभकामनाएँ

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने चिरहुला नाथ मंदिर में भगवान हनुमान की विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विवाह उपरांत चिरहुला दर्शन के लिए आए परिवारों से भेंट कर उन्हें शुभकामना दी और उनके सुखद दांपत्य जीवन की कामना की।

एम्स भोपाल में छात्रों द्वारा 'हाउस ऑफ क्लब्स' की शुरुआत ,तनावमुक्ति, रचनात्मकता एवं सामुदायिक जुड़ाव की दिशा में अनूठा कदम

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान के छात्रों द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए हाउस ऑफ क्लब्स की शुरुआत की गई है – यह एक छात्र-प्रेरित, जीवंत मंच है जिसका उद्देश्य रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, समुदाय में एकजुटता लाना और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। इस पहल को संस्थान के प्रशासन द्वारा पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यह अभिनव प्रयास प्रो. (डॉ.) अजय सिंह, कार्यकारी निदेशक, एम्स भोपाल के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के अंतर्गत संभव हो पाया है। संस्थान द्वारा जिम क्षेत्र के समीप स्थित स्टूडेंट काउंसिल कक्ष को विशेष रूप से छात्रों के लिए समर्पित किया गया है, जो अब इस पहल का केंद्र बन चुका है। हाउस ऑफ क्लब्स में वर्तमान में डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, ड्रामा एवं मूवी क्लब, बुक एवं मैगज़ीन क्लब, तथा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी क्लब जैसे क्लब्स शामिल हैं। इन क्लबों का उद्देश्य छात्रों को अकादमिक जीवन से परे अपने रुचियों का विकास करने का अवसर प्रदान करना तथा मेडिकल शिक्षा की कठिनाइयों के बीच तनाव से राहत देना है। इस पहल की शुरुआत एक ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण म्यूज़िक जैमिंग सेशन के साथ हुई, जिसमें छात्रों ने उमंग एवं उत्साह के साथ भाग लिया। यह आयोजन आने वाली रचनात्मक और जीवंत गतिविधियों की शुरुआत का प्रतीक बना। इस अवसर पर छात्र परिषद के सदस्यों ने प्रशासन, विशेष रूप से प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने छात्र-केन्द्रित गतिविधियों के लिए एक समर्पित मंच की आवश्यकता को पहचाना और छात्रों के समग्र विकास हेतु यह सशक्त कदम उठाया। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने इस अवसर पर कहा- एम्स भोपाल में हमारा मानना है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, शैक्षणिक उत्कृष्टता जितना ही महत्वपूर्ण है। हाउस ऑफ क्लब्स छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है जहाँ वे खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं और कक्षा से परे भी विकास कर सकते हैं। मैं हमारे छात्रों को इस पहल के लिए बधाई देता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि संस्थान उनका हरसंभव सहयोग करता रहेगा।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य अमले को दिलाई तंबाकू नियंत्रण की शपथ

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा से वर्चुअल माध्यम से राज्यभर के स्वास्थ्य अमले को तंबाकू नियंत्रण की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर सहित अनेक जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण है। तंबाकू नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में पूरे राज्य में जनजागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें आज की पीढ़ी को नशे की प्रवृत्तियों से बचाकर स्वस्थ और समर्थ राष्ट्र की नींव रखनी है।उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे तंबाकू और नशे के अन्य रूपों के दुष्प्रभावों के प्रति समुदाय को जागरूक करें, ताकि यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बने। उन्होंने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और समृद्धि का सवाल है। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य अमले को यह शपथ दिलाई कि वे न केवल स्वयं तंबाकू और नशे से दूर रहेंगे, बल्कि समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

अवैध रूप से परिवहन की जा रही 14 नग सागौन इमारती वनोपज जप्त

रायसेन (निप्र)। मुख्य वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल श्री राजेश कुमार खरे के निर्देशन एवं वनमण्लाधिकारी सामान्य रायसेन श्रीमति प्रतिभा शुक्ला के मार्गदर्शन में दिनांक 19.05.2025 की रात को परिक्षेत्र सिलवानी पूर्व अंतर्गत वन स्टाफ द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान लकड़ी चोरों के विरूद्ध बडी कार्यवाही करते हुये अवैध रूप से सागौन इमारती 14 नग 0.125 घनमीटर, 2 मोटर सायकल पर अवैध परिवहन करते हुये 2 आरोपियों को पकड़ा गया। बीती रात परिक्षेत्र पूर्व सिलवानी में वन स्टाफ द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान परिसर बेरखेडी के वन कक्ष क्रमांक पीएफ 592, ग्राम मनकापुर रोड पर 2 वाहन मोटर सायकल से अवैध रूप से सागौनी इमारती वनोपज 14 नग, 0.125 घनमीटर, 2 मोटर सायकल पर अवैध परिवहन करते हुये आरोपी रामबाबू आदिवासी आ डब्बल सिंह निवासी बीकलपुर एवं आरोपी अखलेश आदिवासी आ. मुन्ना आदिवासी निवासी बीकलपुर को गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 47381 / 23 दिनांक 20.05.2025 एवं वन अपराध प्रकरण क्रमांक 47381 / 24 दिनांक 20.05.2025 पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

पिपलबर्रा गांव में जल संकट गहराया, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इंजीनियर ललित पर लापरवाही का आरोप, ठेकेदार को पुन: कार्य सौंपने की मांग

बैतूल। चिचोली विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पिपलबर्रा गांव में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य और जल संकट को लेकर ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया। ग्रामवासियों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीएचई विभाग के इंजीनियर ललित गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने ठेका रद्द होने के बावजूद बीते दो वर्षों से पानी की आपूर्ति कर रहे ठेकेदार को पुन: कार्य सौंपने की मांग भी की है। ग्रामवासी रम्मू, मुन्ना, रामदयाल के अनुसार वर्ष 2020 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिपलबर्रा गांव में देशमुख कृषि एजेंसी शाहपुर को नल-जल योजना का ठेका दिया गया था। परंतु गांव में जलस्रोत बोरवेल न होने के कारण ठेकेदार कार्य प्रारंभ नहीं कर सका। ग्रामीणों ने बार-बार पीएचई विभाग के इंजीनियर ललित गुप्ता से संपर्क किया पर उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2022 में विभाग द्वारा गांव में बोर करवाया गया, लेकिन इसी बीच विभाग ने बिना कारण बताए ठेका निरस्त कर दिया। परिणामस्वरूप गांव में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांववासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इंजीनियर को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह आज तक गांव नहीं पहुंचे। इसी दौरान पूर्व ठेकेदार ने मानवीय आधार पर दो वर्षों से अपने खर्च पर गांव में पानी की आपूर्ति जारी रखी है। ग्रामीणों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कलेक्टर से मांग की है कि उसे पुन: कार्य सौंपा जाए और अधूरा कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने पुराने कलेक्ट्रेट भवन का किया औचक निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार को पुराने कलेक्ट्रेट भवन में संचालित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कार्यालय परिसर में एक आईटी सेंटर अनधिकृत रूप से संचालित हो रहा है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रभाव से सेंटर को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बिना वैध अनुमति के संचालित किसी भी आईटी सेंटर को तत्काल बंद कराया जाए तथा संबंधित संचालक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को अधिकृत लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ही सेवाएं प्रदान की जाएं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री राजीव कहार एवं तहसीलदार श्री पाथे भी उपस्थित रहे। जिले में संचालित सभी अनाधिकृत आईटी केंद्रों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं।

साथी अभियान का क्रियान्वयन 15 अगस्त तक

विदिशा (निप्र)। निराश्रित बच्चों के लिए साथी अभियान जिले में संचालित किया जा रहा है जो 15 अगस्त तक क्रियान्वित किया जाएगा। नालसा व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशो में और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जाकिर हुसैन के मार्गदर्शन में क्रियान्वित साथी अभियान के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री एनएस तोमर ने बताया कि लावारिस बच्चों को चिन्हित कर उनके आधार कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें शासन की योजना का लाभ दिलाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथी अभियान के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यो के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। उक्त कमेटी में तहसीलदार, डीपीओ, सीएमएचओ, महिला एवं बाल विकास अधिकारी और अधिवक्ता कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए है। साथी अभियान के लिए गठित समिति के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित कर अभियान के क्रियान्वयन व आयोजन की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 मई से 26 जून तक आधार कार्ड से वंचित निराश्रित बच्चों

का सर्वे एवं पहचान कार्यक्रम आयोजित कर सर्वे किया जाएगा एवं उनसे मांग भराने की जानकारी संकलित की जाएगी। साप्ताहिक आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाएगी। आवश्यकतानुसार चिन्हित क्षेत्रो में आधार रजिस्ट्रेशन केम्प आयोजित किए जाएंगे ताकि आधार कार्ड बनाने की कार्यवाही सुगमता से पूरी हो सके।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मयूर डेरी का किया निरीक्षण, पनीर किया जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मीना कुमारे, जूनियर सप्लाय ऑफीसर धर्मदास पनिका, आरक्षक गिरिराज धाकड़ द्वारा खापा आठनेर स्थित मयूर डेरी में छापा मारा गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेरी का निरीक्षण किया और पनीर की जप्ती की। 15 किलों पनीर लूज के 2 नमूने लिए गए। लिए गए सैंपल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री शंभू दरबार के सानिध्य में हो रहे श्री शिव महाशक्ति महायज्ञ के दर्शन करने उमड़ा जन सैलाब

हीरालाल गोलानी सोहागपुर । श्री शंभू दरबार पलाश कालोनी सोहागपुर के सानिध्य में माखननगर के सांगाखेड़ा नर्मदा नदी के तीरे हो रहे श्री शिव महाशक्ति महायज्ञ के चतुर्थ दिवस पर संध्याकाल में यज्ञ नारायण की आरती में शामिल होने को जन-सैलाब उमड़ा इस जन-सैलाब के बीच ब्रह्मलीन गुरुदेव पंडित मनमोहन मुद्गलजी महाराज को याद करके ग्रामीण जनता-जनार्दन भावुक हो गई। उल्लेखनीय है कि आयोजन कि ब्रह्मलीन पंडित मनमोहन मुद्गल ने मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में करीबन 25 महायज्ञों का कुशलतापूर्वक संम्पन्न कराया था। गुरूजी के ब्रह्मलीन होने के उपरांत श्री शंभू दरबार के गद्दा नशीन पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल ने इस वर्ष नर्मदा नदी तीरे उक्त यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। भक्त गण उसी प्रकार पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल को पूज्यनीय श्रध्दा प्रदान करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मलीन पंडित मनमोहन मुद्गल से प्राप्त करते थे। इसी क्रम में प्रवचनों की श्रंखला में पंडित अखिलेश्वरी देवी जालोन उत्तर प्रदेश ने अपने धार्मिक उद्बोधन में जनता-जनार्दन का मग्न कर दिया। वहीं सायंकालीन यज्ञ नारायण की आरती डॉ- श्रीराम सरकार ठाकुर के सानिध्य में हो रही है। श्री शिव शक्ति महायज्ञ में वृंदावन की रासलीला का आनंद नागरिक एवं मातृशक्ति ले रही हैं । ज्ञातव्य है कि 18 से 28 मई को यज्ञ का समापन होगा। इस अवसर पर महायज्ञ स्थल से विशाल चुनरी यात्रा मां नर्मदा तट पहुंचेगी । इसके साथ ही भंडारे का कार्यक्रम किया जाएगा । आयोजन समिति ने महायज्ञ में उपस्थित होकर धर्म लाभ उठाने का आग्रह किया है।

पीएम टीबी मुक्त अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने एसटीएस बरेली को किया सम्मानित

टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने हेतु ल्यूपिन फाउन्डेशन के अधिकारी भी सम्मानित

रायसेन (निप्र)। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान अंतर्गत बुधवार को राज्य स्तरीय 100 दिवसीय नि:क्षय शिविर सम्मान समारोह सांदीपनी सभागार राजभवन भोपाल में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा रायसेन जिले से एसटीएस बरेली श्री उमेश शर्मा को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने हेतु ल्यूपिन फाउन्डेशन से श्री राजीव पुरी एवं श्री सुशील डोंगेश्वर को भी सम्मानित किया गया। टीबी मुक्त अभियान माह मई 2025 से समस्त जिले में आयोजित किया जाएगा जिसमें हाईरिस्क जनसंख्या को चिन्हांकित कर शिविर लगाकर स्क्रीनिंग, नाट जांच, मोबाईल डाग्यनोस्टिक वैन से एक्सरे आदि जांच कर टीबी पाए जाने पर उपचार प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही उपचार के दौरान नि:क्षय पोषण योजना अंतर्गत प्रतिमाह एक हजार रू पोषण सहायता राशि बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी और प्रतिमाह फूड बास्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 में प्रदेश में टीबी उन्मूलन करना है। कार्यक्रम में जिले से जिला क्षय अधिकारी डॉ यशपाल सिंह बाल्यान, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ सोमन दास, जिला एनसीडी डॉ सौरभ जैन तथा जिला कार्यक्रम सन्वयक डॉ आरती गंगवार द्वारा सहभागिता की गई।

जल है जीवन की धारा, कल का यही सहारा

विदिशा (निप्र)। जल है जीवन की धारा, कल का यही सहारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा सवंर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है। यह अभियान जन-जन के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रगति पर है। अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर नये तालाब बनाये जा रहे, वहीं दूसरी ओर पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुँओं का जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। नदियों को साफ-स्वच्छ एवं जल एकत्रित करने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले तालाबों, जल स्त्रोतों तथा देवालयों में जल संरक्षण के कार्य भी किये जा रहे हैं। यह जन प्रतिनिधियों, स्थानीय समुदाय, जनभागीदारी, आमजन और सरकार के संयुक्त प्रयास से संचालित होगा, जिसमें मशीन, सामग्री व श्रम का समुचित नियोजन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के ग्राम पंचायतों में नवीन खेत तालाब के कार्य किये जा रहें हैं ।

राइट क्लिक

क्या माओवाद अब सचमुच अंतिम सांसें गिन रहा है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं। संपर्क- 9893699939 ajaybokil@gmail.com

क्या देश में माओवाद (नक्सलवाद) अब अंतिम सांसें गिर रहा है? क्या देश के 12 राज्यों में लाल कॉरिडोर बनाने का आधी सदी पुराने 'लाल' सपने को संकल्प ने मिट्टी में मिला दिया है? क्या नक्सल प्रभावित जिलों में अब स्थायी शांति लौटने की आस बढ़ गई है या फिर यह एक अस्थायी शांति है, कुछ समय बाद माओवादी नए सिरे से अपने काम में लग जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि हाल में एक शीर्ष माओवादी नेता बसवराजू के मारे जाने से माओवादियों को तगड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके तीन नेता माडी हिडमा, भूपति और प्रभाकर अभी भी सक्रिय हैं। माओवादियों की संख्या अब घटकर भले आधी रह गई हो, लेकिन 'देश में प्रतिक्रियावादी (लोकतांत्रिक) शासन प्रणाली को खत्म कर सशस्त्र क्रांति के जरिए 'जन सरकार' स्थापित करने का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और आम जनता में माओवादियों की घटती साख के चलते उनके हौसले ढीले पड़ गए हैं।

देश में मोदी सरकार और कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों में भाजपा सरकारें आने के बाद माओवादियों के सामने दो ही विकल्प बचे हैं या तो वो सुरक्षा बलों से लड़ते हुए मारे जाएं या फिर आत्म समर्पण कर दें। सरकार की यह नीति 'लाठी और गाजर' वाली है। पिछले एक साल में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में जितनी संख्या में माओवादी या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने आत्म समर्पण किया है, उससे लगता है कि देश में राजनीतिक-सामाजिक बदलाव का माओवादियों का सपना अब अतीत की बात बन जाने वाला है। क्योंकि पचास साल के सशस्त्र संघर्ष और सैकड़ों मौतों के बाद भी इससे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सका है। अब तो युवाओं में भी ऐसी कथित क्रांति कोलेकर वो रूचि नहीं रह गई है, जो किसी जमाने में हुआ करती थी। ऐसे में नक्सली आंदोलन जो कभी देश के 12 राज्यों में फैला था, अब महज 6 जिलों तक सिमट गया है। जो आंदोलन कभी किसानों और आदिवासियों को उनके हक और शोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था, वह खुद रंगदारी, हत्याओं और अराजकता में तब्दील हो गया। माओवादी केवल एक लक्ष्य में आंशिक रूप से कामयाब रहे और वो है कि आधुनिक विकास की किरणें दूरदराज के इलाकों तक न पहुंचने देना। लेकिन इसके बदले में आम लोगों को क्या मिला? जो युवा कभी माओवाद के हिंसक रास्ते पर चल पड़े थे, उनके हिस्से में थोथे आत्म संतोष या हताशा के अलावा क्या आया? माओवादियों ने घने जंगलों, दूरदराज के इलाकों, दुर्गम पहाड़ियों आदि को अपने छिपने ठिकाना इसलिए बनाया था ताकि पुलिस और सुरक्षा बल वहां तक न पहुंच सकें। जंगलों में उन्होंने किसी हद तक अपना राज कायम भी कर लिया था। जब भी इस पर कोई आंच आती दिखती, वो इसका जवाब आतंक से देते। जिनमें सुरक्षा बलों पर घातक हमले हों या फिर मुखबिरी के आरोप में स्थानीय निवासियों की बेरहम हत्याएं हों। हालांकि जिस मूल कम्युनिस्ट विचारधारा से माओवाद का जन्म हुआ था, उसे मानने वाली और राजनीतिक मुख्यि धारा में शामिल पार्टियों ने माओवादी हिंसा से दूरी बना ली थी, लेकिन माओवादी संघर्ष के प्रति उनके मन में साफ्ट कॉर्नर, अर्बन नक्सलियों द्वारा उनका मार्गदर्शन, आर्थिक और नैतिक सहयोग बरकरार था। यह बात अलग है कि जिस माओवाद का खयाली पुलाव ये पकाते रहे हैं, उसे असली माओवादी चीन ने भी पीछे छोड़ दिया है।

माओवाद दरसअल पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से जमीनदारों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के रूप में 70 के दशक में शुरू हुआ था। तब इसके पीछे चारू मुजुमदार, कनु सान्याल जैसे साम्यवादियो का राजनीतिक दर्शन भी था। इसे चीन का भी समर्थन था। मान गया कि पुरानी और सामंती व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीकों के बजाए रक्त क्रांति से ही बदला जा सकता था। तब के युवा, जिनका आजादी के बाद देश में बने हालात से मोहभंग हो रहा था, इस माओवादी विचार की तरफ तेजी से आकृष्ट हुए। यह समझे बगैर कि भारत और चीन की तासीर में बहुत अंतर है। माओंवादियों ने जिस 'जन संघर्ष' का नारा दिया, वह हमेशा एक सीमित दायरे से आगे नहीं बढ़ पाया। कांग्रेस की सरकारों ने माओवादियों के प्रति नरम या मिला जुला रवैया अपनाया हुआ था, बावजूद इसके कि छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में माओवादियों ने हमला कर राज्य में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का सफाया कर दिया था। अलबत्ता आंध्र और तेलंगाना में जरूर कुछ सख्तीत दिखाई। यह भी कोशिश हुई कि माओवादियों से बातचीत कर उन्हें मुख्य धारा में लौटाया जाए। लेकिन वह भी नाकाम रही।

इस मामले में मोदी सरकार और भाजपा का रवैया बहुत साफ है। उनका मानना है कि गोली का जवाब गाल सहलाना नहीं हो सकता। माओवाद को खत्म करने के लिए उसकी जड़ों पर चोट जरूरी है। इसलिए सुरक्षा बलों का नक्सल प्रभावित राज्यों में संयुक्त अभियान शुरू किया गया। उन्हें घने जंगलों में घुसने के लिए अत्याधुनिक उपकरण, ट्रेनिंग और हथियार दिए गए। उससे भी बढ़कर माओवादियों के खात्मे में उन पूर्व माओवादियों का भरपूर सहयोग लिया गया जो आत्म समर्पण कर चुके थे। उनकी अलग से फोर्स बनाकर माओवाद के खात्मे के काम पर लगाया गया। 'डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड' के रूप में उनकी भर्तियां पुलिस बल में की गईं। इनमें महिला पूर्व नक्सली भी शामिल हैं। यह रणनीति सबसे कारगर साबित हुई। आज जो बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, उनमें इन पूर्व माओवादियों का बड़ा योगदान है। इसके अलावा सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की प्रभावी और सकारात्मक नीति भी माओवाद की कमर तोड़ने में कारगर साबित हुई है। सालों जंगलों की खाक छानने वाले कई नक्सली अब मुख्य धारा में लौटकर सुकून के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। एक आत्म समर्पित माओवादी का यह बयान अहम है कि नई पीढ़ी की दिलचस्पी अब क्रांति से ज्यादा मोबाइल, बाइक और गर्लफ्रेंड में है।

दरअसल बीती 21 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों ने 'आपरेशन ब्लैक फारेस्ट' के तहत 27 माओवादियों को घेरकर मार गिराया। इनमें माओवादियों के संगठन सीपीआई (माओवादी) का महासचिव और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू भी शामिल था। बसवराजू एक इंजीनियर था और माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर नक्सली बना था। उस पर सरकार ने 1 करोड़ रू. का इनाम रखा था और जो 150 जवानों की हत्या का आरोपी था। उसी ने और सीपीआई (माओवादी) की सशस्त्र शाखा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) को मजबूत करने का काम किया था। पीएलजीए का गठन 2000 में कई छोटे-छोटे नक्सलियों के गुटों के विलय के बाद हुआ था। बसवराजू के खात्मे को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'नक्सलवाद ख़त्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया। इसी अभियान में 54 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके पहले दूरस्थ कुरेगुट्टा पहाड़ी मे माओवादियों के ठिकानों को घेरकर सुरक्षा बलों ने 31 माओवादियों को मौत के घाट उतारा था। उनसे बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस वर्ष के पहले चार महीनों में 700 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस बीच सुरक्षा बलों का दावा है कि माओवादियों का 'रेड कॉरिडोर' तो दूर, खुद माओवाद चार राज्यों के छह जिलो तक सीमित रह गया है। ये राज्य हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड। सरकार के मुताबिक़ देश भर में माओवाद प्रभावित ज़िलों की संख्या 126 से घट कर अप्रैल 2018 में 90 रह गई थी, जुलाई 2021 में ऐसे ज़िलों की संख्या 70 हो गई और अप्रैल 2024 के आंकड़ों के अनुसार माओवाद प्रभावित ज़िलों की संख्या महज 38 रह गई है।

तो क्या अब सचमुच माओवाद अंतिम सांसें गिन रहा है? इसका उत्तर 'हां' में देना अभी जल्दबाजी होगी। कुछ लोग सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुरक्षाबलों को नुकसान भी झेलना पड़ा है। साथ ही माओवाद पर लगाम कसने का राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या माओवादी अब थक चुके हैं? यह अभी गारंटी से नहीं कहा जा सकता। कुरैगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के घिरने के बाद माओवादियों ने छग सरकार के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था, जिसे सरकार ने यह कहकर ठुकरा दिया कि या तो नक्सली हथियार डालें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। नक्सलियों की इस पहल को उनके बिखर रहे संगठन को फिर से जमाने के लिए जरूरी इंटरवल के रूप में भी देखा गया। इसका अर्थ यही नहीं कि उनकी कमर पूरी तरह टूट गई है।

कहीं न कहीं से उन्हें ऊर्जा अभी भी मिल रही है। जानकारों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन का भी एक सुव्यवस्थित ढांचा है, एक तय व्यवस्था है जिसमें एक के जाने से दूसरे के लिए जगह बनती है। यानी एक बसवराजू मरेगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। लिहाजा माओवाद को खत्म करना है तो किसानों, आदिवासियों और शोषित समूहों की उन समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा, जिनकी वजह से माओवाद पनपा। जहां तक मप्र की बात है तो माओवाद राज्य के केवल छग और महाराष्ट्र से लगे कुछ जिलों तक सीमित है, लेकिन वहां भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है। विकास की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नक्सलियों का असर घटता जा रहा है।

कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक आनंद सिंहा का निधन

भोपाल। कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक आनंद नारायण सिन्हा का शुक्रवार सुबह 4:44 बजे निधन हो गया । वे काफी समय से अस्वस्थ थे। उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्रामघाट पर किया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र आनंद राम सिन्हा ने दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्कृतिकर्मी मौजूद थे।

ससुराल या पैतृक पंचायत में नहीं होगा तबादला

- **पंचायत में दस साल से पदस्थ सचिवों को सबसे पहले हटाएगी सरकार**

भोपाल (नप्र)। तबादले के लिए बचे नौ दिन की समय सीमा के बीच पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के लिए तबादला नीति जारी की है। इस नीति में कहा गया है कि एक ही पंचायत में दस साल की समय अवधि पूरी कर चुके पंचायत सचिवों के तबादले सबसे पहले होंगे। कोई भी पंचायत सचिव अपनी पैतृक पंचायत या ससुराल में पदस्थ नहीं किया जा सकेगा।

साथ ही अंतर जिला तबादले के लिए जहां से तबादला होना है और जहां के लिए होना है, उन दोनों ही जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की एनओसी होना अनिवार्य तय किया गया है।

पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर जारी एक अन्य निर्देश में कहा गया है कि नियमित पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति में जिले के भीतर ट्रांसफर में यह व्यवस्था भी लागू रहेगी कि जो पंचायत सचिव एक ही ग्राम पंचायत में पिछले दस साल या अधिक समय से पदस्थ हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा।

जिला संवर्ग में कार्यरत सचिवों की संख्या का 10 प्रतिशत ही ट्रांसफर इस कैटेगरी में किया जा सकेगा। जिन सचिवों को एक ही पंचायत में दस साल हो चुके हैं उनका तबादला पहले किया जाएगा।

जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद

उमंग सिंघार बोले- बीजेपी निवेश की नहीं, इवेंट की सरकार

निवेश प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक सीमित, मंत्री सारंग का जवाब- नकारात्मक बात करना इनकी आदत

भोपाल (नप्र)। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को भोपाल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेंगलुरु दौरे और 'इन्वेस्ट इन एमपी' कार्यक्रम को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

सिंघार ने कहा कि सरकार ने 7,935 करोड़ के निवेश और 18,975 नौकरियों का वादा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये निवेश सम्मेलन वैसा ही है जैसे शादी के कार्ड बांटे जाएं और दूल्हा-दुल्हन का अता-पता ही न हो।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ वादों का मेला- नेता प्रतिपक्ष ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों की घोषणा हुई, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। सिंघार ने सवाल उठाया कि क्या GIS विकास का मंच है या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का तमाशा।

वहीं साल 2019 से 2024 के बीच मध्यप्रदेश को महज 4,563 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश मिला। जबकि महाराष्ट्र को 6.71 लाख करोड़ और कर्नाटक को 4.27 लाख करोड़ का। जब निवेश नहीं आ रहा तो सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए क्या कर रही है।

दावोस से गायब रहा मध्यप्रदेश- नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विश्व आर्थिक मंच दावोस 2025 में देश के कई राज्यों को आमंत्रित किया गया, लेकिन मध्यप्रदेश को नहीं। महाराष्ट्र को वहां 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। जब दुनिया के सामने खुद को रखने का मौका था, तब एमपी नदारद क्यों। वहीं 'आउटलुक बिजनेस' की मार्च 2025 की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश स्टार्टअप आउट परफॉर्मर रैंकिंग में 15वें स्थान पर रहा। भोपाल और इंदौर जैसे शहर बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई से कोसों दूर हैं। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वे पलायन करेंगे ही।

एमएसएम को तवज्जो नहीं: 18 लाख इकाइयों पर महज 1,785 करोड़- उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18.10 लाख एमएसएम हैं, जिनमें 17.9 लाख माइक्रो इकाइयां हैं, लेकिन इन पर खर्च सिर्फ 1,785 करोड़ का बजट तय किया गया है। सिंघार ने कहा कि सरकार बाहर से निवेश बुला रही हैं, लेकिन अपने ही उद्योगों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

नकारात्मक बात करना कांग्रेस नेताओं की आदत: मंत्री सारंग

नेता प्रतिपक्ष सिंगार के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि नकारात्मक बात करना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो प्रयास किए हैं उसका एक सकारात्मक परिणाम निकला है, चाहे वह रीजनल इन्वेस्टर समिट हो या फिर भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। हर एक निवेश का प्रयास जो सरकार ने किया है उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। कांग्रेस के नेता यह भूल जाते हैं कि उनके किसी बयान से प्रदेश या देश का सम्मान भी बिगड़ता है। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तो मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें वहां भेजा है और मध्य प्रदेश के हित का ध्यान सभी को रखना चाहिए। लेकिन राजनीतिक में कांग्रेस के नेता यह भूल जाते हैं। मैं दृढ़ता के साथ यह बात कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में मोहन यादव की सरकार ने अच्छा काम किया है और लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है।

पीएचई के इंजीनियर-कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी

भोपाल (नप्र)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 54 मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, 35 उपयंत्री तथा 19 मानचित्रकार, समयपाल, हेल्पर, चौकीदार, सहायक ग्रेड स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इनमें भोपाल से एनएस जौहरी को मुख्य अभियंता ग्वालियर और संजय कुमार को इंदौर का प्रभारी मुख्य अभियंता बनाया है।

54 मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री स्थानांतरित

पीएचई विभाग द्वारा 54 मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन और सहायक यंत्रियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। जिन मुख्य अभियंता के ट्रांसफर हुए हैं उसमें एनएस जौहरी को भोपाल से मुख्य अभियंता ग्वालियर, आरएलएस मौर्य प्रभारी मुख्य अभियंता को ग्वालियर से अधीक्षण यंत्री पन्ना, संजय कुमार अधीक्षण यंत्री को भोपाल से प्रभारी मुख्य अभियंता इंदौर, महेंद्र सिंह कार्यपालन यंत्री पन्ना से प्रभारी अधीक्षण यंत्री रीवा, व्हीके छारी कार्यपालन यंत्री ग्वालियर से प्रभारी अधीक्षण यंत्री मुरैना, रामकुमार सिंह राजपूत कार्यपालन यंत्री भिंड को प्रभारी अधीक्षण यंत्री ग्वालियर पदस्थ किया गया है। इसी आदेश में कार्यपालन यंत्री संजीव कुमार गुप्ता को भोपाल से प्रभारी अधीक्षण यंत्री प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल, दिलीप कुमार जैन को प्रमुख अभियंता कार्यालय से प्रभारी अधीक्षण यंत्री प्रभारी अधीक्षण यंत्री भोपाल रीजन, मोनिका सप्रे इंदौर से प्रभारी अधीक्षण यंत्री इंदौर, केएस कुसरे डिंडोरी से सीई आफिस जबलपुर, संतोष साल्वे विदिशा से कार्यपालन यंत्री इंदौर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा सहायक यंत्री मुजीब उल हसन को सिवनी मालवा नर्मदापुरम से प्रभारी कार्यपालन यंत्री नर्मदापुरम, बीएस अचाले प्रभारी कार्यपालन यंत्री खरगोन से प्रभारी कार्यपालन यंत्री आगर मालवा, लखन प्रताप सिंह शिवपुरी से प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्योपुर पदस्थ किए गए हैं।

शुभम अग्रवाल श्योपुर से प्रभारी कार्यपालन यंत्री शिवपुरी, अमित कुमार शाह मऊगंज से प्रभारी कार्यपालन यंत्री अनूपपुर, पवनसुत गुप्ता हरदा से प्रभारी कार्यपालन यंत्री कटनी, प्रदीप कुमार सक्सेना भोपाल से प्रभारी कार्यपालन यंत्री सीहोर, अफजल अमान उल्लाह शहडोल से प्रभारी कार्यपालन यंत्री डिंडोरी, नरेश कुमार भास्कर उज्जैन से प्रभारी कार्यपालन यंत्री हरदा, संजीव कुमार गुप्ता भिंड से प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्वालियर, आशीष मार्तंड रायसेन से प्रभारी कार्यपालन यंत्री भोपाल, वर्षा शिवपुरे इंदौर से प्रभारी कार्यपालन यंत्री खंडवा पदस्थ किया गया है।

अमित सिंह देवास से प्रभारी कार्यपालन यंत्री भिण्ड, नरेश कुवाल, रतलाम से प्रभारी कार्यपालन यंत्री देवास, त्रयंबकेश कुमार द्विवेदी सीधी से प्रभारी कार्यपालन यंत्री सीधी, सुरेश चंद्र

लापता युवक का शव मिला, परिजनों ने थाना घेरा

बहन का दावा; 4-5 युवक बॉक्स में ले जा रहे भाई की लाश, सीसीटीवी आया सामने

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक लापता युवक की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान लालू यादव उर्फ अर्जुन के रूप में हुई है, जो शबरी नगर का निवासी था। युवक की लाश बिलकिसगंज थाना क्षेत्र स्थित एक डैम में तैरती हुई मिली।

परिजनों ने एक कैफे में युवक की हत्या का आरोप लगाया है और इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए थाने का घेराव किया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों ने कमला नगर थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि अगर पुलिस पहले ही कदम उठाती तो युवक की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कैफे से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

बहन का दावा-भाई की हत्या के बाद बॉक्स में रखकर ले गए लाश- मृतक की बहन ममता यादव ने दावा किया है कि लालू यादव को 19 मई की रात नेहरू नगर स्थित पलक कॉम्प्लेक्स में एक कैफे में बुलाया गया था। यह कैफे शुभम नागेश्वर का बताया जा रहा है। ममता के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में मेरा भाई रात 12.19 बजे कैफे के अंदर जाते हुए साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद वह बाहर नहीं आता। वहीं, रात करीब तीन बजे एक और सीसीटीवी में चार-पांच लड़के एक बॉक्स में कुछ उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। उसी बॉक्स में मेरे भाई की लाश थी। इसी फुटेज में शुभम मेरे भाई की शर्ट और बाइक के साथ बाहर निकलता दिख रहा है।

पुलिस को 2 दिन पहले दे चुके थे सीसीटीवी फुटेज, नहीं हुई कार्रवाई- परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही पुलिस को संदेहियों की सीसीटीवी फुटेज सौंप दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ममता का आरोप है कि, हम लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं, मगर ना तो आरोपियों को बुलाया गया और ना ही उनसे पूछताछ की गई। उल्टा पुलिस हमें ही टालती रही। शुभम ने ही मेरे भाई को फोन कर बुलाया था। उसकी बहन रक्षा और मां भी उस समय पास में थीं। उसी रात के बाद भाई लापता हो गया और अब उसकी लाश मिली है।

शुभम शर्ट बदलकर बाहर निकला

ममता यादव के अनुसार, कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि रात करीब तीन बजे कुछ युवक एक बॉक्स को कार में रख रहे हैं। उसमें शुभम भी शामिल है। मेरे भाई की शर्ट और जूते शुभम पहने हुए दिख रहा है, लेकिन उसकी पैंट अलग है। साफ है कि यह सब सुनियोजित था। मृतक और शुभम की जान-पहचान 8 साल पुरानी थी।

इससे पहले भी एक बार लड़की भागकर लालू के पास आ गई थी, लेकिन उसके घरवालों ने धमकी दी थी कि शादी नहीं होने देंगे और लालू को मरवा देंगे। पूरे मामले को लेकर एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने कहा,थाना बिलकिसगंज क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान अब गुमशुदा युवक अर्जुन यादव के रूप में हुई है। मर्ग कायम कर लिया गया है। शव करीब दो दिन पुराना लग रहा है। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रधान आरक्षक ने ब्राह्मण समाज पर की विवादित टिप्पणी

टीकमगढ़ में परशुराम सेना ने किया विरोध प्रदर्शन, एसपी से कार्रवाई की मांग

टीकमगढ़ (नप्र)। टीकमगढ़ में एक प्रधान आरक्षक की ओर से सोशल मीडिया पर की गई जातिगत टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने एसपी मनोहर मंडलोई को ज्ञापन सौंपकर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के स्क्रीन शॉट भी एसपी को दिए हैं।

ब्राह्मण समाज पर की विवादित टिप्पणी- राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सौरभ शर्मा ने बताया कि मामला 21 मई 2025 का है। संभाग पुलिस बल सागर के एक सोशल मीडिया ग्रुप में जातिगत आंकड़ों को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट पर कोतवाली टीकमगढ़ में पदस्थ प्रधान आरक्षक मूलचंद्र अहिरवार ने विवादित टिप्पणी की। इसमें ब्राह्मण समाज और पुलिस में कार्यरत ब्राह्मण कर्मियों के परिवारों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गईं।

एडमिन को भी इस मामले का सह-भागीदार बताया- ग्रुप के एडमिन अरविंद अहिरवार, जो टीकमगढ़ यातायात पुलिस में आरक्षक हैं, ने न तो विवादित टिप्पणी को हटाया और न ही टिप्पणी करने वाले को ग्रुप से निकाला। इस कारण परशुराम सेना ने एडमिन को भी इस मामले का सह-भागीदार माना है।